नई दिल्ली
सोमवार 2 फरवरी 2026
फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष,
प्रतिपदा वर्ष : 29, अंक : 290
पृष्ठ 12 मूल्य 2.00

मौसम
अधि. 22
न्यून. 10

हरिभूमि

दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित
समाचार ही नहीं, विचार भी
haribhoomi.com

पीएम मोदी ने बजट पर कहा, देश की 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि यह बजट देश की नारी शक्ति का मजबूत प्रतिबिंब है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार बजट पेश करके नया रिकॉर्ड बनाया है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ₹आज का बजट ऐतिहासिक है; यह देश की नारी शक्ति का शक्तिशाली प्रतिबिंब है। एक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करके नया रिकॉर्ड बनाया है। यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। यह वर्तमान की आकांक्षाओं को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करता है। यह विकसित भारत@2047 की ऊंची उड़ान के लिए मजबूत आधार है।

उन्होंने बजट को रिफॉर्म एक्सप्रेस के लिए नई ऊर्जा और गति प्रदान करने वाला बताया। मोदी जी ने कहा कि यह बजट ट्रस्ट-बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन-सेंट्रिक इकोनॉमी की दृष्टि को साकार करता है। इसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, महंगाई नियंत्रित रखने के साथ उच्च कैपेक्स और उच्च विकास का समन्वय है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत अब सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प है। हाल के बड़े ट्रेड डील्स का अधिकतम लाभ भारत के युवाओं और एमएसएमई को मिले, इसके लिए बजट में प्रमुख कदम उठाए गए हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया गया है। सनराइज सेक्टर्स जैसे बायो-फार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनरल्स पर जोर, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाई-टेक टूल मैन्युफैक्चरिंग और चैंपियन एमएसएमई बनाने जैसे कदम अभूतपूर्व हैं। एमएसएमई और छोटे-कुटीर उद्योगों को मिला समर्थन उन्हें लोकल से ग्लोबल बनाने में नई ताकत देगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वाटरवेज का विस्तार, हाई-स्पीड रेल ▶▶शेष पेज 5 पर

अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के बीच भारत ने की बांग्लादेश के बजट में 50% की कटौती

विदेश मंत्रालय के बजट में भूटान ने मारी बाजी, 2 हजार करोड़ से अधिक का आवंटन

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए आवंटित नहीं की गई कोई धनराशि

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विदेश मंत्रालय को 1600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल करीब 22 हजार 118.97 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया है। जिसकी एक खास बात यह है कि इस बार भारत ने अपने कुछ निकट पड़ोसी और सहयोगी मित्र देशों के लिए बजट के माध्यम से अपनी तिजोरी के ताले खोल दिए हैं। जबकि कुछ देशों की अस्वीकार्य गतिविधियों ▶▶शेष पेज 5 पर

भूटान को 2,289, बांग्लादेश को 60 करोड़

बजट दस्तावेज के मुताबिक, भारत ने इस बार बजट में भूटान को सबसे ज्यादा 2 हजार 289 करोड़ रुपए की सहायता राशि का आवंटन किया है। जबकि दूसरी ओर बांग्लादेश में बीते कुछ वक्त से हिंदुओं सहित अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य लोगों के खिलाफ जारी भीषण हिंसा ▶▶शेष पेज 5 पर

▶▶ टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं ▶▶ 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा

रक्षा, शिक्षा, हेल्थ पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम, फिर भी बाजार धड़ाम!

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए लोकलुभावन योजनाओं से परहेज किया और 'सुधार एक्सप्रेस' को जारी रखने की घोषणा की। सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए किसानों, युवाओं और छोटी कंपनियों पर विशेष ध्यान देने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दिया और सुधारों का खाका पेश किया। कुल मिलाकर, यह बजट आत्मनिर्भरता, तेज विकास और चुनावी राज्यों में निवेश पर केंद्रित है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, रोजगार बढ़ेगा और भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत बनेगा। इधर, बजट को बाजार समझ नहीं पाया और धड़ाम हो गया। कुछ ही पल में निवेशकों ने लाखों करोड़ रुपए डूब गए।

बजट में खास

- 85 मिनट के भाषण में सीतारमण ने इस बार नहीं किया किसी कवि और कविता का उल्लेख
- नई ग्रामीण रोजगार योजना 'वीबी-जी राम जी' के लिए 95,000 करोड़ आवंटित
- वित्त मंत्री ने पांच चिकित्सकीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का रखा प्रस्ताव
- संशोधित आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव
- बजट में छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना की घोषणा
- पुनर्खरीद से होने वाली प्राप्ति पर अब लगेगा 'पूंजीगत लाभ कर'
- बजट में अगले पांच साल में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव
- केंद्र सरकार प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के पास पांच विवि टाउनशिप स्थापित करेगी
- मंत्रियों, मंत्रिमंडल सचिवालय और पीएमओ के खर्च के लिए 1,102 करोड़
- बाबुओं के प्रशिक्षण के लिए 299 करोड़ रुपए, प्रशासनिक सुधारों को 65 करोड़
- विधि मंत्रालय को मतदाता पहचान पत्रों के लिए मिले 250 करोड़
- खेल सामग्री क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपए, खेलो इंडिया को फिर से सर्वाधिक आवंटन

कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट...तीन कर्तव्यों से है प्रेरित केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 की मुख्य बातों पर एक नजर...

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 प्रस्तुत किया। नवनिर्मित कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है।

पहला कर्तव्य – उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल-पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना

दूसरा कर्तव्य- भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना।

तीसरा कर्तव्य - सरकार की सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल- यह सुनिश्चित करना कि सार्थक भागीदारी के लिए प्रत येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच उपलब्ध हो।

बजट अनुमान

- गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
- सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपए और दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
- गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड रुपए है जिसमें से केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियाँ 26.7 लाख करोड़ रुपए हैं।
- कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ रुपए है जिसका पूंजी व्यय करीब 26.1 लाख करोड़ रुपए है।
- बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वर्ष 2025-26 के बजट में संशोधित राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट अनुमान जीडीपी के 4.4 प्रतिशत के समान है। ▶▶शेष पेज 5 पर

सात रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण

- बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर करने की रणनीति) की घोषणा। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अगले पांच वर्ष के लिए दस हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव।
- तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (एन.आई.पी.ई.आर.) के निर्माण तथा सात मौजूदा संस्थानों के उन नयन के लिए बायोफार्मा केन्द्रित नेटवर्क।
- एक हजार से अधिक मान यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स स्थलों का नेटवर्क बनाया जाएगा।
- उपकरण और सामग्री बनाने, फुलस्टेक इंडिया आई.पी. डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा।
- अप्रैल 2025 में आरंभ इलेक ट्रॉनिक्स कलपुर्जे विनिर्माण ▶▶शेष पेज 5 पर

पूंजी सामान क्षमता मजबूत करना

- डिजिटल रूप से सक्षम ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में दो स्थानों सी.पी.एस.ई. द्वारा हाईटेक टूल रूप स्थापित किए जाएंगे, जो उच्च गुणवत्ता के कलपुर्जों का बड़े पैमाने पर और कम लागत से स्थानीय स्तर पर डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे।
- उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत सी.आई.ई. के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निर्माण संवर्धन और अवसंरचना उपकरण योजना(सी.आई.ई.) शुरू की जाएगी।
- पांच वर्ष की अवधि में दस हजार करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना लाने प्रस्ताव।

वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा

- रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानवनिर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय ▶▶शेष पेज 5 पर

चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव

- खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव। इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला-एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा।
- इससे वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी और प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन को समर्थन मिलेगा।

लीगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजना

अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए लागत स्पर्धा और दक्षता में सुधार के लिए दो सौ लीगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजना लाने का प्रस्ताव।

चैंपियन एस.एम.ई. बनाना और सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन

- एम.एस.एम.ई. को चैंपियनों के रूप में विकास करने में सहायता के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण- दस हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एस.एम.ई. ग्रोथ फंड शुरू करने का प्रस्ताव।
- दो हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ वर्ष 2021 में बनाए गए आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन जारी रहेगा।
- विशेष रूप से टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में कॉर्पोरेट मित्र कार्डर विकसित करने के लिए आई.सी.ए.आई., आई.सी.एस.आई, आई.सी.एम.ए.आई. जैसे व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अवसंरचना को ठोस प्रोत्साहन

- वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव।
- समर्पित आर.ई.आई.टी. स्थापित करने के जरिए सी.पी.एस.ई. की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के पुनर्वक्रण की प्रक्रिया तेज करने का प्रस्ताव।
- पूर्वी भारत में डानकूनी से पश्चिमी भारत के सूरत को जोड़ने के लिए नए समर्पित माल गलियारे बनाए जाएंगे।
- जलचर और अंगुल जैसे खनिज समृद्ध और कलिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोडने के लिए ओडिशा में एनडब्ल्यू-5 से शुरुआत के साथ अगले पांच वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे।
- अपेक्षित श्रम शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
- इनलैंड जलमार्गों और तटीय पोत परिहवन की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत से बढाकर वर्ष 2047 तक 12 प्रतिशत करने के लिए तटीय कार्गो प्रोमोशन स्कीम आरंभ की जाएगी।
- सी-प्लेन के स्वदेशी निर्माण ▶▶शेष पेज 5 पर

वित्त मंत्री ने बजट में सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए बीआरओ को दिए 7 हजार 394 करोड़ रुपए

डीआरडीओ को 29 हजार करोड़ का बजट, स्वदेशी उद्योगों से हथियार खरीद पर खर्च होगी 75% धनराशि

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद के पटल पर रखे गए बजट में जहां एक ओर रक्षा क्षेत्र को हर लिहाज से चाक-चौबंद बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। तो, वहीं दूसरी ओर वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच आत्मनिर्भरता के साथ सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत खरीद के लिए आवंटित की गई 2 लाख 19 हजार 306.47 करोड़ रुपए की धनराशि में से 75 फीसदी घरेलू उद्योगों से हथियार खरीद पर खर्च करने के लिए निर्धारित की गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में 29 हजार 100.25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में डीआरडीओ के 26 हजार 816.82 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। जबकि इस बार मौजूदा आवंटन का एक बड़ा हिस्सा यानी 17 हजार 250.25 करोड़, संगठन की पूंजीगत मद के लिए रखने का प्रावधान ▶▶शेष पेज 5 पर

अब चारों खाने चित होंगे भारत के दुश्मन...

ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7.85 लाख करोड़ के साथ रक्षा बजट में 15% से अधिक का ऐतिहासिक उछाल

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेरने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को संसद में पेश किए गए देश के पहले बजट में सशस्त्र सेनाओं की युद्धक क्षमता को स्वदेशीकरण के साथ-साथ शत प्रतिशत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से रक्षा बजट (वित्त वर्ष-2026-27) को ऐतिहासिक रूप से 15.19 फीसदी तक बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 6 लाख 81 हजार 210 करोड़ रुपए था। रक्षा बजट का सबसे आकर्षक बिंदु सेना, वायुसेना और नौसेना के तीव्र आधुनिकीकरण के लिए भविष्य में की जाने वाली सैन्य हथियारों और जंगी प्लेटफॉर्म की खरीद (पूंजीगत मद) से जुड़ा है। जिसके लिए वित्त मंत्री ने पहले के मुकाबले 21.84 फीसदी की भारी-भरकम वृद्धि के साथ 2 लाख 19 हजार 306.47 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसकी मदद से भारतीय ▶▶शेष पेज 5 पर

भारतीय रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने 2,93,030 करोड़ का आवंटन

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए ऐतिहासिक आवंटन किया गया है। रेल मंत्रालय को पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए रिकॉर्ड 2। लाख 93 हजार 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि कुल आवंटन 2,78,000 करोड़ (लगभग 2.78 लाख करोड़) रखा गया है। यह अब तक का सबसे अधिक बजट है, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, क्षमता विस्तार और यात्री सुरक्षा पर केंद्रित है। रेलवे को आर्थिक विकास और लॉजिस्टिक्स दक्षता का प्रमुख इंजन बनाने के उद्देश्य से यह निवेश किया जा रहा है। उच्च गति कनेक्टिविटी, फ्रेट मूवमेंट, हाई-डेंसिटी कॉरिडोर की भीड़ कम करना और आधुनिक ट्रेनों व स्टेशनों के पुनर्विकास से यात्री अनुभव बेहतर होगा।

सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यावरण-अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। इन्हें 'ग्रोथ कनेक्टर्स' कहा गया है, जो अंतर-शहर यात्रा समय को काफी कम करेंगे और मल्टीमॉडल यातायात को सुगम बनाएंगे।

ये कॉरिडोर हैं:

- मुंबई–पुणे
- पुणे–हैदराबाद
- हैदराबाद–बेंगलुरु
- हैदराबाद–चेन्नई
- चेन्नई–बेंगलुरु
- दिल्ली–वाराणसी
- वाराणसी–सिलीगुड़ी

दक्षिण भारत में चेन्नई-बेंगलुरु-हैदराबाद हाई-स्पीड नेटवर्क से 'साउथ हाई-स्पीड ट्रायंगल' (या डायमंड) बनेगा, जो प्रमुख आर्थिक और ▶▶शेष पेज 5 पर

कहा, 1.70 लाख करोड़ रु. से अधिक उर्वरक सब्सिडी, किसानों की लागत में राहत

कृषि बजट 1.32 लाख करोड़ रूपए का होना स्वागत योग्य किसानों की प्रगति और विकास का बजट: मंत्री चौहान

बोले, ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 21% की उल्लेखनीय वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत की नींव और मज़बूत होगी

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की मज़बूत नींव रखने वाला ऐतिहासिक और अभूतपूर्व ▶▶शेष पेज 5 पर

गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला – सबका बजट

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि यह बजट विशेष रूप से गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला– इन सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं से गरीबी लगातार कम हो रही है और यह बजट गरीब को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

लखपति दीदी और 'शीमार्ट': ग्रामीण बहनों को उद्यमी बनाने की दिशा में बड़ा कदम

उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए बजट में सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर 'शीमार्ट' की व्यवस्था की गई है। हर जिले में बहनों के उत्पादों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, जहाँ स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण बहनों द्वारा तैयार उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पशुपालन, कृषि से जुड़ी गतिविधियों और अन्य कार्यों में लगी बहनें अब केवल ▶▶शेष पेज 5 पर

ग्रामीण विकास बजट में 21% की वृद्धि

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस वर्ष 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और कृषि विभाग को जोड़कर देखें तो ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का सम्मिलित बजट अब 4 लाख 35 हजार 779 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो गांव और किसान के ▶▶शेष पेज 5 पर

दो विदेशी नागरिक किए गिरफ्तार

एनसीआर में सक्रिय मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने पश्चिमी दिल्ली में दो विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के साथ मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 'सिंथेटिक' मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले इस अभियान को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों के पास से एमडीएमए और 'एक्स्टसी' की गोलियां जब्त की गई। आरोपियों की पहचान नाइजीरियाई नागरिक प्रेशियस उर्फ प्रॉमिस (26) और घाना के नागरिक जेफ्री बोटेंग उर्फ माइक (44) के रूप में हुई है। दोनों पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार, राजधानी भर में 'सिंथेटिक' मादक पदार्थों की आपूर्ति में शामिल तस्करों की गतिविधियों के बारे में मिली सूचना के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं। अभियान के दौरान, पुलिस ने प्रेशियस के पास से 270 ग्राम एमडीएमए और लगभग 18 ग्राम वजन की 40 'एक्स्टसी' गोलियां बरामद कीं और जेफ्री बोटेंग के पास से अतिरिक्त 72 ग्राम एमडीएमए बरामद किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम को सूचित किया गया था कि मादक पदार्थ की आपूर्ति करने के लिए प्रेशियस मोहन गार्डन के पास पहुंचेगा। पुलिस ने बताया कि छापेमारी दल को घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस के अनुसार, रात 11:50 बजे एक व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचा तो उसे पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान प्रेशियस उर्फ प्रॉमिस के रूप में हुई और तलाशी के दौरान उसके पास से मादक पदार्थ और 'एक्स्टसी' की गोलियां बरामद हुईं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रीशियस को पिछले साल नौ दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह 2022 में मेडिकल वीजा पर भारत आया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी और वह देश में अवैध रूप से रह रहा था। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वह पश्चिमी दिल्ली में अपने साथियों से मादक पदार्थ खरीदता था और फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके भारतीय ग्राहकों को इसकी आपूर्ति करता था। पकड़े जाने से बचने के लिए वह संदेशों को डिलीट कर देता था।" पुलिस ने आगे बताया कि जांच के बाद 30 जनवरी को उत्तम नगर में जेफ्री बोटेंग को गिरफ्तार किया गया। वह 2018 में पर्यटक वीजा पर भारत आया था और वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी यहां रुका रहा। पूछताछ के दौरान, बोटेंग ने स्वीकार किया कि वह प्रेशियस के साथ मिलकर मादक पदार्थ गिरोह चला रहा था और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मादक पदार्थों की आपूर्ति कर रहा था।

यातायात पुलिसकर्मियों को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के दो और आरोपी अरेस्ट

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर जबरन वसूली करने वाले दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी उन गिरोहों से जुड़े थे जो यातायात पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाकर गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्ड करके तथा उनमें हेरफेर करके उन्हें ब्लैकमेल करते थे। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही दोनों मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या 10 हो गई है और इनमें कथित गिरोह सरगना जीशान अली तथा राजकुमार उर्फ राजू मीना भी शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) संजीव कुमार यादव ने एक बयान में कहा, "आरोपियों को अपराध शाखा द्वारा एक संगठित यातायात धोखाधड़ी और जबरन वसूली नेटवर्क की जारी जांच के तहत चलाए गए दो अलग-अलग अभियानों में गिरफ्तार किया गया।" अधिकारी ने बताया कि पहले अभियान में पुलिस ने आमिर चौधरी उर्फ सिकंदर को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि सिकंदर, पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके जीशान अली के संगठित अपराध गिरोह का कथित सदस्य है। उन्होंने कहा कि यह गिरोह आधिकारिक ड्यूटी के दौरान गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्ड करके और बाद में ब्लैकमेल करने के लिए उनका इस्तेमाल करके यातायात पुलिसकर्मियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों से पैसे वसूलने में शामिल था। अधिकारी ने कहा, "दूसरे अभियान में गिरोह के सरगना राजकुमार उर्फ राजू मीना के प्रमुख सहयोगी संजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया।" उन्होंने बताया कि राजकुमार मीना और रियाजुद्दीन ने गुप्ता को आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय यातायात पुलिसकर्मियों के वीडियो रिकॉर्ड करने और उनमें हेरफेर करने का प्रशिक्षण दिया तथा बाद में पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलने के लिए उनका इस्तेमाल किया। पहला मामला यातायात पुलिसकर्मियों की शिकायत पर शुरू किया गया था, जब एक हल्के वाणिज्यिक वाहन के चालक ने फर्जी "03 मार्च" स्टिकर प्रदर्शित करके और चालान से छूट का दावा करते हुए जांच से बचने का प्रयास किया था। जांच के दौरान पुलिस ने व्यावसायिक वाहन चालकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्हाट्सएप समूहों का विश्लेषण किया और एक संगठित अपराध गिरोह का खुलासा किया जो एक समानांतर अवैध प्रणाली चला रहा था। आरोप है कि इस गिरोह ने व्यावसायिक वाहन चालकों और मालिकों को धोखा दिया, साथ ही चालान की कार्यवाही के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करके और बाद में उन्हें संपादित करके झूठी शिकायतें दर्ज कराने की बात कहकर यातायात पुलिसकर्मियों से पैसे की उगाही की। पुलिस उपायुक्त ने कहा, "जीशान अली को इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता माना गया, जिसके बाद पिछले साल मुख्य आरोपी समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।" उन्होंने कहा, "दूसरा मामला राजकुमार उर्फ राजू मीना का है। वह 2015 से सक्रिय एक आदतन अपराधी है और अपने साथियों के साथ मिलकर ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाता था। उसे पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था।" राजकुमार मीना को आठ दिसंबर को और सह-आरोपी मुकेश उर्फ पकोड़ी को 11 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि संजय गुप्ता और आमिर चौधरी को 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है।

दिल्ली में ओलावृष्टि और बारिश हुई दर्ज

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शनिवार देर रात कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि ने मौसम ने अपने तेवर दिखाए है। रविवार वीकेंड की सुबह हवा में ठंडक का अहसास कम होने महसूस किया गया। सुबह से ही आसमान पर बादलों का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन शाम तक कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी ही दर्ज हो सकी। हालांकि ओलावृष्टि और बारिश के बाद भी दिल्ली में न्यूनतम तापमान डबल डिजिट यानी 10 डिग्री से अधिक ही दर्ज हुआ, जबकि शनिवार को यह सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ था। प्रादेशिक मौसम विभाग दिल्ली के अनुसार वीकेंड रविवार को न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि शनिवार को यह आंकड़ा महज 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा था। रविवार को अधिकतम तापमान भी बढ़कर 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जबकि शनिवार को यह 21.5 डिग्री सेल्सियस था। आंकड़े बताते है कि हल्की ओलावृष्टि और बारिश के बाद भी रविवार को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। आईएमडी के अनुसार सोमवार से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आसमान पर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं तेज हवाएं बह सकती है। इसके साथ ही रविवार को कड़ाके की ठंड से मिली राहत मंगलवार तक गायब होने के साथ ही तापमान पिल लुढ़कने की पूरी संभावना है। अनुमान है कि मंगलवार से अगले तीन चार दिन न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आस पास दर्ज होगा। लेकिन अभी वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी कहना आसान नहीं हैं।

बजट 2026 विकसित भारत 2047 की दिशा में एक दूरदर्शी, समावेशी और निर्णायक दस्तावेजः खंडेलवाल

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत 2047 की दिशा में एक दूरदर्शी, समावेशी और निर्णायक दस्तावेज साबित होगा। खंडेलवाल ने कहा कि बजट देश के व्यापारियों, उद्यमियों, निवेशकों और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आत्मविश्वास से भरा सकारात्मक संदेश देता है। आर्थिक विकास के साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की भावना इस बजट को विशिष्ट बनाती है। एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष बल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में आसान ऋण उपलब्धता, अनुपालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटल सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नयन तथा औपचारिकरण को प्रोत्साहन जैसे प्रावधान छोटे उद्योगों और व्यापारियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बजट में एमएसएमई के लिए की गई घोषणाएं रोजगार सृजन, उद्यमिता को प्रोत्साहन और भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में निर्णायक साबित होंगी। बुनियादी ढांचे के विकास, लॉजिस्टिक्स की दक्षता, विनिर्माण, निर्यात, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उपभोग आधारित विकास पर निरंतर ध्यान देने से देश के व्यापार और वाणिज्य को व्यापक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह देश की आर्थिक बुनियाद को और सुदृढ़ करते हुए विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। खंडेलवाल ने कहा कि बजट के विभिन्न प्रावधानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी आह्वान से सीधा जुड़ाव भारत के निर्यात को नई मजबूती देगा और भारतीय उत्पादों के लिए नए वैश्विक बाज़ार खोलने में सहायक सिद्ध होगा। यह बजट अपने समावेशी दृष्टिकोण, ठोस कार्ययोजना और स्पष्ट दिशा के माध्यम से देश की आर्थिक नींव को और अधिक मजबूत करता है।

मुखर्जी नगर में रोडरेज की घटना, वकील को डंडे से पीटा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर के पास रोडरेज की एक घटना में, दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले एक वकील पर पांच से छह लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया और डंडे से पीटा। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 25 जनवरी को रात करीब 8.45 बजे इलाके के एक रेस्तरां के पास हुई।

उत्तर प्रदेश के नोएडा एक्सटेंशन निवासी 29 वर्षीय शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि एक संकरी गली में उनकी कार को काले रंग की एक 'थार' द्वारा रोके जाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद उनपर हमला किया गया। प्राथमिकी के अनुसार, "मैं एक मुवक्किल से मिलने मुखर्जी नगर गया था और अपनी एसयूवी चला रहा था, तभी एक मोड़ पर हरियाणा पंजीकरण नंबर वाली काले रंग की थार अचानक मेरे वाहन के सामने रुक गई।" वकील ने दावा किया कि 'थार' ने उनकी कार का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया था और लगभग पांच मिनट तक इंतज़ार करने के बाद, वह किसी तरह अपनी कार को दाहिनी ओर से निकालने में कामयाब रहे, जिसके बाद थार चालक उन्हें गालियां देने लगा। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, "जब मैं अपनी कार से उतरा और गाली-गलौज का विरोध किया, तो थार के चालक ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। जब मैंने उससे कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तो आरोपी ने अपनी गाड़ी की खिड़कियां बंद कर लीं, फोन पर बात की और थोड़ी दूर आगे जाकर रुक गया और फिर से गाली-गलौज करने लगा।" शिकायतकर्ता ने बताया कि तब तक घटनास्थल पर भीड़ एकत्र हो चुकी थी और किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे उलझें नहीं और पुलिस को सूचना दें। शिकायतकर्ता का एक दोस्त भी उस वक्त तक घटनास्थल पर पहुंच चुका था और वे दोनों पुलिस को फोन करने के लिए अपनी कार की ओर वापस जा रहे थे, तभी 'थार' चालक अपने पांच-छह साथियों के साथ कथित तौर पर वापस आ गया। प्राथमिकी के अनुसार, "उन सभी के पास डंडे थे और उन्होंने अचानक पीछे से हम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने हमें जान से मारने के इरादे से डंडे से हमारे सिर पर कई बार वार किए।" पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि उसके दोस्त पर भी हमला किया गया और उसके भी सिर में चोटें आईं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलने पर एक पीसीआर वैन मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों के बयान दर्ज करने के लिए एक टीम को अस्पताल भेजा गया।

अधिकारी ने कहा, "हमारी टीम वहां पहुंची और पीड़ितों के बयान दर्ज करने की कोशिश की।

बुराड़ी की बदहाली से परेशान लोगों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन, आप-भाजपा को ठहराया दोषी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

बुराड़ी मुख्य 100 फुटा रोड़ की कई सालों से हुई पड़ी दुर्दशा से परेशान लोगों ने कांग्रेस नेता नेता मंगेश त्यागी की अगुवाई में रविवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आप पार्टी के विधायक संजीव झा का पुतला दहन किया। मंगेश की अगुवाई में केनरा बैंक के पास जुटे लोगों ने बुराड़ी रोड ही नहीं बल्कि पूरे बुराड़ी क्षेत्र की बदहाल को लेकर जमकर विधायक झा पर अपना गुस्सा निकाला। मंगेश त्यागी ने कहा कि यहां की जनता ने तीन बार भारी बहुमत से संजीव झा को विधायक बनाया। बदले में विधायक झा ने लोगों को विकास के नाम पर बदहाल के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज बुराड़ी का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां गहरे गहरे गड्ढे ना खुदे पड़े हो। बुराड़ी मुख्य रोड़ लगभग पांच साल से बेहद बुरी हालात में है। त्यागी ने कहा कि बुराड़ी की दर्जनों कालोनियों, बुराड़ी गांव, स्वरूप नगर बुराड़ी मार्ग, इब्राहिम पुर रोड, कादीपुर रोड, बुराड़ी पुस्ता रोड़, जगतपुर रोड़, पेप्सी रोड़ सहित सभी रोड़ बुरी हालत में है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां से वाहन तो क्या आदमी पैदल भी निकल जाए। यहां 24 घंटे जाम में फंसे लोग विधायक संजीव झा को कोसते रहते है। स्थानीय निवासी श्याम शर्मा का आरोप है कि क्षेत्र की दुर्दशा के लिए आम आदमी पार्टी के साथ ही भाजपा भी जिम्मेदार है। यहां से स्थानीय सांसद मनोज तिवारी भी तीसरी बार जीते है, लेकिन उन्होंने बुराड़ी को अछूत समझ रखा है। स्थानीय महिला सुनीता रावत ने कहा कि मैं वर्तमान सीएम रेखा गुप्ता से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि एक बार बिना किसी पूर्व सूचना के बुराड़ी में आ जाए और अपनी आंखों से देख ले कि हम जीते जी कैसे नर्क भोग रहे है। हरमिंदर ने बताया कि बुराड़ी का दौरा तो खुद एलजी विनय कुमार सक्सेना ने किया था। उन्होंने उस समय आम पार्टी की सरकार को कई दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन एलजी के आदेश निर्देश सब ठेंगे पर रहे कुछ नहीं हुआ उल्टा हालात और ज्यादा बिगड़ गए है।

हाउस टैक्स के खिलाफ लांमबंद हुए दिल्ली के ग्रामीण, गांवों से जुड़े मुद्दों पर जतायी एकजुटता

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

■ सोलंकी के नेतृत्व में 360 गांवों के प्रतिनिधियों ने मंगोलपुर कलां गांव में की बैठक

दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के खाप प्रमुखों ने एमसीडी के शीर्ष नेताओं के साथ हाल ही में लाल डोरा हाउस टैक्स माफी पर चर्चा की। पालम 360 के प्रमुख सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में दिल्ली के 360 गांवों के प्रतिनिधियों ने रविवार को मंगोलपुर कलां गांव में बैठक की और राष्ट्रीय राजधानी के लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों में हाउस टैक्स माफी के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की, जो एक मांग है जो उन्होंने लंबे समय से सरकार के समक्ष रखी है। ग्रामीण प्रमुखों की यह बैठक सोलंकी के नेतृत्व में गांवों के एक प्रतिनिधिमंडल और मेयर राजा इकबाल, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा और सदन के नेता सहित एमसीडी के शीर्ष नेताओं के बीच हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक और चर्चा के बाद हुई है। सोलंकी के अनुसार, ग्रामीणों ने रविवार को इस मुद्दे पर भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए बैठक की, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर एमसीडी नेतृत्व के साथ हाल की बातचीत सकारात्मक रही, दावा किया कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के पक्ष में समाधान निकालने का आश्वासन दिया था।

ग्राम खाप प्रमुखों की बैठक के बाद, ग्रामीण नेता ने कहा कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल मेयर राजा इकबाल, नेता सदन परवेश वहीं,स्थायी समिति के अध्यक्ष से समाधान पर चर्चा करने के लिए मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इस मामले पर पूरे गांवों से सामूहिक राय ली है।

हाउस टैक्स माफी के अलावा, ग्रामीण क्षेत्र के नेताओं ने 360 गांवों से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें सर्कल दरों के संशोधन, लंबित मुद्दों जैसे सर्कल दर संशोधन, भूमि आवंटन और 74/4 और 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित स्वामित्व, वैकल्पिक भूखंडों का आवंटन शामिल हैं।

सोलंकी ने कहा कि जल्द ही गांवों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल से मिलने और उनसे दिल्ली के गांवों के मुद्दे पर चल रहे कार्यों को तेजी से करने का अनुरोध करने पालम 360 खाप के प्रमुख ने कहा कि इन मुद्दों पर पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की गई थी, और विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्र को आश्वासन दिया गया था कि काम किया जाएगा।

सोलंकी ने यह भी कहा कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र को उम्मीद है कि दिल्ली के गांवों के लाल डोरा या विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों में भवन उप-नियम लागू नहीं होने चाहिए।गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी के गांव कई मुद्दों से जूझ रहे हैं, विशेष रूप से नागरिक समस्याएं और बुनियादी सुविधाओं की कमी, जिसने इन स्थानों को कहीं नहीं छोड़ा है, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है, क्योंकि वे टूटी सड़कों, स्वच्छता की कमी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के बीच संघर्ष कर रहे हैं।

हत्या के मामले में वांछित आरोपी आठ साल बाद किया गिरफ्तार

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने 2018 में हत्या के एक मामले में करीब आठ साल से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2018 को चोरी के बाद उत्तरपूर्व दिल्ली में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में सीमापुरी थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी ने कहा कि वह बार-बार अपना ठिकाना बदलकर और भूमिगत रहकर गिरफ्तारी से बच रहा था।

चोरी के दौरान, आरोपी ने अपने साथियों के साथ एक घर में प्रवेश किया। जब घर के मालिक की नींद खुली और उसने चोरों का मुकाबला किया, तो उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जांच के दौरान सह-आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी भागने में कामयाब रहा और कई वर्षों तक फरार रहा। पुलिस ने बताया कि 31 जनवरी को मुख्य आरोपी के संभावित ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद, उसका पता लगाने के लिए एक टीम गठित की गयी। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जांचदल को मुख्य आरोपी के हरियाणा के फरीदाबाद में होने का पता चला और फिर उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के सामने उसने 2018 के हत्या मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी काफी समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था।

पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने 2017 में कई डकैतियां की थीं, जिनमें उत्तरी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में हुई एक डकैती और हत्या की घटना भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि सीमापुरी में हमले में जिस व्यक्ति की जान गयी उसे आरोपी जानता था और सुनियोजित चोरी के दौरान उसकी हत्या कर दी गयी।

बजट में दिल्ली पुलिस के लिए 12 हजार 503 करोड़ रुपये आवंटित

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली पुलिस के लिए 12,503.65 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गयी है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4.79 प्रतिशत अधिक है। इस कोष का इस्तेमाल नियमित खर्चों और विभिन्न योजनाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें एनसीआर क्षेत्र में एक आदर्श यातायात प्रणाली का विकास और एक उन्नत संचार नेटवर्क का विकास शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात प्रबंधन समेत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। संचार अवसंरचना का उन्नयन, नवीनतम तकनीक का समावेश, यातायात सिग्नल लगाना और कर्मियों को प्रशिक्षण देना भी इसके दायित्व का हिस्सा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली पुलिस को आवंटित बजट 11,931.66 करोड़ रुपये था, जिसे आगामी वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 12,503.65 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, "इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है, खासकर युवाओं के लिए रोजगार सृजन, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और विकास, खेलकूद, विदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने पर छूट आदि।

विधायकों की दो से 14 फरवरी तक परमानंद अस्पताल में वार्षिक स्वास्थ्य जांच होगी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रविवार को कहा कि सभी विधायकों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच दो से 14 फरवरी तक कश्मीरी गेट स्थित परमानंद अस्पताल में दिल्ली सरकार की मौजूदा स्वास्थ्य योजना के तहत की जाएगी। गुप्ता ने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच निवारक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और संस्थागत जिम्मेदारी है, जो सार्वजनिक निकायों के कामकाज में निरंतरता एवं दक्षता सुनिश्चित करने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया निर्धारित सरकारी मानदंडों और समय-सीमा पर की जाने वाली एक नियमित वार्षिक प्रक्रिया है तथा इसमें विधायकों के लिए कोई विशेष व्यवहार, रियायत या नया अधिकार शामिल नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह जांच स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा अधिसूचित वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना के तहत की जा रही हैं। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे लागू प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर अपनी स्वास्थ्य जांच कराएं।

भारतीय संत परंपरा में गुरु रविदास भक्ति, समता और मानव मूल्यों के हैं ध्वजवाहक : नितिन नवीन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

भारतीय संत परंपरा में गुरु रविदास भक्ति, समता और मानव मूल्यों के ध्वजवाहक हैं। यह बात रविवार को संत शिरोमणी गुरू रविदास महाराज की 649वीं जयंती के अवसर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कही। उन्होंने करोलबाग स्थित गुरू रविदास विश्रामधाम मंदिर में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा के साथ पूजा अर्चना की और स्थानीय महिलाओं के सत्संग में सम्मिलित हुए। नितिन नवीन ने मंदिर की आगंतुक पुस्तिका में संत श्री रविदास समाज के नाम शुभकामनाएं लिखीं। समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि आज संत शिरोमणि रविदास जी की पावन जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला है। नवीन ने कहा कि संत रविदास ने अपने विचारों और वाणी से जाति-भेद,ऊंच-नीच और अन्याय का विरोध किया तथा प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने सामाजिक समरसता और सद्भावना के जिस दीप को प्रज्वलित किया, वह देशवासियों के पथ को सदैव आलोकित करता रहेगा। मंदिर प्रबंधन समिति एवं दिल्ली भाजपा नेताओं ने श्री नितिन नवीन का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किया।इस अवसर पर नितिन नवीन के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, सांसद बांसुरी स्वराज, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष लालसिंह आर्या, दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह आदि ने भी मंदिर में पंजा अर्चना की।

नरेला में आयोजित भंडारा एवं शोभायात्रा में शामिल हुए मंत्री इंद्राज

नई दिल्ली। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 649वीं जयंती के पावन अवसर पर रविवार को नरेला स्थित गुरु रविदास मंदिर में आयोजित 31वें भव्य भंडारा एवं शोभायात्रा कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने सहभागिता कर श्रद्धालुजनों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचार समता, सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और भाईचारे पर आधारित हैं, जो आज भी एक समरस, समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में हमें निरंतर प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उल्लेखनीय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर इससे पूर्व दिल्ली सचिवालय में रविन्द्र इंद्राज सिंह के नेतृत्व में एक भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें संत रविदास के विचारों, सामाजिक समरसता और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। मंत्री इंद्राज ने कहा कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और संत रविदास के विचार सरकार की नीतियों और कार्यों के मूल में हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शोभायात्रा और भंडारे में श्रद्धा, सेवा और सामाजिक एकता की अनुपम झलक देखने को मिली।

दिल्ली को नई ऊंचाइयां देने वाला है केंद्रीय बजट: रेखा

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट की सराहना करते हुए इसका खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला है।

मुख्यमंत्री के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतिबिंब है, जो हर नागरिक को सशक्त बनाने, समाज के सभी वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने और देश की सतत व मजबूत आर्थिक

वृद्धि को गति देने का काम करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट तीन स्पष्ट कर्तव्यों पर केंद्रित है। पहला, आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करना, जिसके लिए निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत आधार दिया गया है ताकि विकास व्यापक और टिकाऊ हो सके। दूसरा, देशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना, जिससे आम आदमी का जीवन अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बने। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि विकास और संसाधनों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और 'सबका साथ, सबका विकास' का संकल्प वास्तविकता में बदले। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, खासकर अन्नदाता किसानों, युवा शक्ति, नारी शक्ति और वंचित वर्गों के लिए। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष जोर दिया गया है। घरेलू निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का स्पष्ट रोडमैप भी इस बजट में नजर आता है, जिससे भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे भविष्य के क्षेत्रों में इनोवेशन और विकास को प्रोत्साहित किया गया है। इससे न सिर्फ रोजगार और समृद्धि के नए अवसर खुलेंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता भी और मजबूत होगी। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर जिस स्पष्टता और गंभीरता के साथ बात रखी गई है, वह वास्तव में सराहनीय है। इसी तरह देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोकर उसे मजबूत और आकर्षक पर्यटन उद्योग के रूप में विकसित करने की सोच को भी मुख्यमंत्री ने बेहद प्रभावी बताया।

बजट में दिखती है खेलो इंडिया मिशन की साफ झलक : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि खेलो इंडिया मिशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के विजन की साफ झलक इस बजट में दिखाई देती है। साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विदेश जाने वाले नागरिकों को मिलने वाली रियायतें मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए बड़ी राहत हैं। आपदा प्रबंधन के लिए शहरों को दिए जाने वाले अनुदानों को लेकर उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली को भी खासा लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्यों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान एक सकारात्मक और दूरगामी कदम है, जो सभी राज्यों को विकास की नई गति देगा।

आम बजट देश में सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला : केजरीवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने रविवार को आए आम बजट में रोजगार बढ़ाने, महंगाई कम करने, विदेशों से काला धन लाने और किसानों की आय दोगुनी करने पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया और इस बजट को निराशाजनक बताया है। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का आम बजट देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, लेकिन इस बजट में रोजगार देने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इस दौरान उन्होंने गोवा राज्य की अनदेखी करने पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश का आम बजट आ गया है। आज बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या बेरोजगारी और महंगाई की है, लेकिन रोजगार देने का कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। यह केवल और केवल महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। वहीं, आप के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो सबसे बड़ा वादा किया था, वह यह था कि हम बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब जब सरकार के 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उन 24 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। सरकार को यह बताना चाहिए कि देश के नौजवानों को आगे रोजगार देने के लिए वह क्या योजना बना रही है। सिंह ने पूछा कि किसानों की फसल का दाम दोगुना करने और काला धन लाने के वादे का क्या हुआ। जो लोग भारत के बैंकों का पैसा लूटकर विदेशों में बैठे हैं, उनका क्या हुआ।सरकार को इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। सरकार को बताना चाहिए था कि बजट के जरिए महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठाएगी। टैक्स सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कभी टैक्स बढ़ाती है, तो कभी एकाएक घटा देती है। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करने का काम किया है। अब यह पटरी पर कैसे आएगा।

यादव ने बजट को बताया लोगों के साथ धोखा, दिल्ली के हाथ रहे खाली

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र का बजट लोगों के साथ किया गया धोखा है। क्योंकि केंद्रीय बजट में दिल्ली के हाथ खाली रहे है। बजट में दिल्ली के साल भर दमघोटू प्रदूषण झेलती दिल्ली की जनसंख्या के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाई नही दी,केन्द्र सरकार ने दिल्ली में रोजगार सृजन, युवाओं को अवसर और महंगाई पर नियंत्रण, लोगों की अजीविका के साधन बढ़ाने पर ध्यान न देकर केवल हवा हवाई घोषणा की है। यादव ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पारित बजट के बाद दिल्ली के लिए बजट आवंटन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, मूलभूत सुविधाओं और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही आश्वस्त दिखाई नही दी। ऐसे में दिल्ली की जनता की उम्मीदें और जरूरतें आगामी वित्त वर्ष में कैसे पूरी होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता ने केन्द्र प्रशासित राज्यों को 1.4 करोड़ के बजट पर सिर्फ गोलमोल बाते करती दिखाई दी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दिल्ली को मोदी सरकार ने बजट में कुछ खास नही दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने की दिशा में केंद्रीय बजट में कोई पहल दिखाई नही देती। यादव ने कहा कि मेट्रो के चौथे और पांचवें फेज की जो घोषणा और बजट की घोषणा पहले हो चुकी है, आर.के. आश्रम से इन्द्रप्रस्थ सेन्ट्रल विस्टा कारिडोर पर सिर्फ फंड बढ़ाकर वाहवाही लूटने का काम किया है। साईकल ट्रैक, स्मार्ट शहर, पैदल यात्री के लिए पथ आदि से दिल्ली की 75 प्रतिशत गरीब और मध्यम वर्गीय जनता का क्या मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को 12,503.65 करोड़ आवंटित किया गया है। इतने बड़े बजट के बाद क्या केन्द्रीय गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजधानी में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने में कामयाब हो सकेंगे, या अपराधी खुले आम अपने मकसद को यू ही अंजाम देते रहेंगे।

विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी है केंद्रीय बजट : विजेंद्र

नई दिल्ली। दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रविवार को वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए लगातार नौवें केंद्रीय बजट पर उन्हें बधाई देते हुए इसे 'विकसित भारत' के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने के साथ-साथ लघु एवं मध्यम उद्योगों को सुदृढ़ करने, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने तथा विश्वास-आधारित शासन के माध्यम से अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करता है। यह बजट उच्च विकास दर को समावेशी विकास के साथ संतुलित करते हुए समाज के सभी वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। विधानसभा अध्यक्ष ने अवसंरचना क्षेत्र में 12.2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का स्वागत करते हुए कहा कि यह विशाल निवेश आधुनिक एवं प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत भौतिक और डिजिटल आधार तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि अवसंरचना पर निरंतर बल से रोजगार सृजन को गति मिलेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और विभिन्न क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा, जिससे देश की समग्र आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के दूरदर्शी नेतृत्व और 2047 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के संकल्प को साकार करने की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

केंद्रीय बजट पर लोगों की मिली जुली राय, किसी को लगा बढ़िया, किसी ने गिनाई कमियां

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 पेश हो गया है जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पावर सेक्टर से जुड़े दिल्ली के इंटेलीसमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी और सीईओ अनिल रावल का कहना है कि केंद्रीय बजट 2026 भारत के बेहतर भविष्य को स्पष्ट दिखाने वाला है। खासकर पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड के प्रस्तावित पुनर्गठन से विकास के लिए तैयार वित्तीय इकोसिस्टम बनाने की लंबी अवधि की एक मजबूत रणनीति को स्पष्ट दर्शा रहा है। रावल ने कहा कि यह संस्थाएं न केवल पावर सेक्टर के लिए प्रमुख ऋणदाता हैं, बल्कि व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। पावर सेक्टर विकसित भारत 2047 के लिए डिजिटल रूप से आधुनिक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। कार मैकेनिक अभिषेक झा का कहना है इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर मोदी सरकार को अभी बहुत कुछ करना होगा। दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर फोकस बढ़ाना जरूरी है। अभिषेक ने कहा कि मिडिल क्लास के लोगों को सबसे बड़ा सपना अपना चार पहिया वाहन का होता है। ऐसे में अगर सरकार ईवी वाहन पर सब्सिडी बढ़ाए और उसका भुगतान भी जल्द हो, कल पुर्जे सस्ते होने चाहिए। अनुबंध पर कार्य करने वाली नेहा का कहना है कि बजट से कुछ बेहतर होने की उम्मीद तो की जा सकती है। बजट से सब खुश हो यह कभी संभव नहीं होता, क्योंकि कि सबका अपना अपना नफा नुकसान होता है। हम मध्यम वर्गी युवा है तो मोदी सरकार व दिल्ली की भाजपा सरकार से सरकारी नौकरी की उम्मीद तो करते ही हैं। रिक्शा चालक हेमंत का कहना है कि बजट वजट हमारी समझ से परे और सिर से ऊपर से निकलने वाली चीज है। हम गरीबों को बस दो वक्त की रोटी आराम से कमाने का माहौल मिले, महंगाई कम हो और आसानी से बीमारी का अस्पताल में इलाज हो जाए। ऐसा ही कुछ फल विक्रेता जीतू का कहना है, कि महंगाई बहुत ज्यादा है उसे कम करने के लिए बजट में क्या किया है तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन यह तो सच्चाई है कि महंगाई ने बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रखा है, अगर मोदी सरकार ने इसमें कुछ राहत दी है तो अच्छी बात है। गृहिणी रेखा धीरज पाल का कहना है कि बजट का सबसे अधिक असर हम गृहणियों पर ही पड़ता है, क्योंकि रसोई चलाने से लेकर बच्चों के खर्चे सब का समाना हमें ही करना पड़ता है। बजट ठीक हो सकता है लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्द बाजी होगा, क्योंकि कई बार बजट और वास्तविकता में जमीन आसमान का फर्क होता है। छात्र विनय कुमार का कहना है बजट अच्छा है, रेहड़ी पटरी से लेकर सर्व समाज, देश की रक्षा सुरक्षा, बुर्जग, छात्र, गृहणी आदि सब का ख्याल रखा गया है। वहीं दिव्यांग हरीश का कहना है कि बजट में इस बार भी कुछ नया नहीं हैं। हम दिव्यांगों को बजट से बहुत उम्मीद थी कि हमारे लिए कोई ऐसी योजना होगी जिससे हम सरकार पर निर्भर न होकर स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके। फोटोग्राफर सतपाल मदान का कहना है कि हमारी समझ से बजट परे की बात है, सीधा सीधा बताओ हमें क्या मिला। बजट में फोटोग्राफी से जुड़े समान सस्ते होंगे तभी हमें कुछ फायदा मिलेगा। क्योंकि महंगाई कोई कम ता हो नहीं रही है, ऐसे में अगर आज पेश बजट कुछ राहत देने वाला साबित होना चाहिए।

खबर संक्षेप

कंपनी कर्मी ने फंदा लगाकर की खुदखुशी

गुरुग्राम। सेक्टर-14 थाना एरिया के राजीव नगर में कंपनी कर्मी ने फंदा लगाकर अपनी जान गवां दी।

सूचना मिलने पर पुलिस ने एफएसएल व फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को मोर्चरी में भेजा। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जानकारी अनुसार, बिहार के कैमूर निवासी मणि चौबे (25) पिछले दो माह से राजीव नगर की गली-3 में एक किराए के कमरे में रह रहा था।

पति से कहासुनी, महिला ने फंदा लगाकर की खुदकुशी

गुरुग्राम। उद्योग विहार थाना के डूंडाहेड़ा में पति से कहासुनी होने

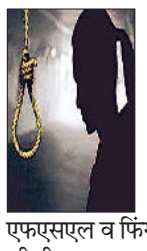

पर एक महिला ने फंदा लगाकर की खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर उद्योग विहार थाने की पुलिस ने एफएसएल व फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को मोर्चरी में भेजा। बिहार के बांका निवासी दीप कुमारी (27) अपने पति व दो बच्चों के साथ डूंडाहेड़ा गांव में किराये पर रहती थी। उसका पति उद्योग विहार क्षेत्र में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है।

ठगी का काम करने वाला आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद। नौकरी का झांसा देकर विदेश बुलाकर साईबर ठगी

का काम करने के आरोप में फरीदाबाद साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने एक व्यक्ति को काबू किया है। पुलिस के अनुसार सेक्टर-78 फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जुलाई 2025 में उसके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, जे थाईलैंड में उच्च वेतन पर नौकरी देने का लालच दिया। ठगों ने उसको आने को कहा और बाद में वर्क वीजा में बदलाव करवाने बारे कहा। ठगों ने अगस्त 2025 में उसके पास बैकांक का टिकट भेजा और उसे बैकांक आने को कहा। बैकांक पहुंचने के बाद उसे एक गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया।

बजट 2026-27: भाजपा ने बजट को सराहा, कांग्रेस ने बकवास बताया

हरिभूमि न्यूज ⏭ गाजियाबाद

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वार्षिक बजट पेश कर दिया है। बजट पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के नेताओं ने जहां बजट को विकास परक बजट बताया है, तो विपक्ष ने इसे अब तक का सबसे घटिया बजट बताया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने केंद्रीय बजट 2026 को नए भारत की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि यह बजट विकास, विश्वास और समावेशी प्रगति का संतुलित रोडमैप है। उन्होंने कहा है कि मध्यम वर्ग को राहत, किसानों को संबल, महिलाओं व युवाओं को नए अवसर और रोजगार सृजन पर स्पष्ट फोकस इस बजट को ऐतिहासिक बनाता है। बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को तेज गति देगा।

विकास और प्रगति देने वाला बजटः सरदार इंद्रजीत, कांग्रेस बोली- फर्जी बजट

मेरठ मण्डल अर्बन कमेटी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल सरदार इंद्रजीत सिंह टीटू ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि केंद्र की मौजूदा सरकार केवल आज को लेकर बजट पर फोकस नहीं करती। सरकार आने वाले भविष्य में हम कैसे अच्छे परिणाम ले सकते हैं इसको लेकर बजट पर काम करती है । 2026 भारत की मजबूत नींव कैसे होगी विकास और विश्वास प्रगति का संतुलित रोडमैप है विशेष तौर से मध्यम वर्ग को राहत, किसानों को संबल, महिलाओं व युवाओं को नए अवसर और रोजगार सृजन पर स्पष्ट फोकस करके बनाया गया है बुनियादी ढांचे, को मजबूत करने शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश देश आत्मनिर्भर कैसे होगा। इसपर लक्ष्य ज्यादा किया गया है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने मोदी सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का ये बजट फर्जी है। बजट के नाम पर मोदी सरकार ने देशवासियों को झुनझुना थमाया है। शर्मा ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

किया गया है इससे खासकर मध्यम वर्ग को भारी निराशा हुई है। ये वर्ग सरकार से इनकम टैक्स में रियायत की उम्मीदें लगाए बैठा था। लेकिन उसकी उम्मीदें धरी रह गईं। बजट को दिशाहीन और फर्जी बताते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि ना तो युवा, किसान और महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ है और ना ही महंगाई, बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए बजट में कोई कदम उठाया गया है।

आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं का बजट

भाजपा नेता जयकमल अग्रवाल ने कहा है कि यह बजट विशेष रूप से आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस किया गया है। यह बजट कुल 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस बजट में 7 नए रेल कोरिडोर का ऐलान किया गया है वहीं आम आदमी को ध्यान में रखते हुए गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में एक और बड़ी राहत विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स कम करके दी है। सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत टीसीएस को 5 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत कर दिया है, इससे 3 प्रतिशत की सीधी टैक्स की छूट मिली है इससे विदेश में पढ़ने वाले छात्रों और विदेश में इलाज कराने वाले मरीजों पर वित्तीय बोझ काफी कम होगा। भाजपा के महानगर प्रवक्ता प्रदीप चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026 देश की आर्थिक मजबूती, समावेशी विकास और सामाजिक संतुलन को सुदृढ़ करने वाला सशक्त दस्तावेज है।

पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का सशक्त ब्लूप्रिंट है केंद्र सरकार का आम बजट

विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में निर्णायक बजटः राव नरबीर सिंह

धर्मेंद्र कौशिक ⏭ गुरुग्राम

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने रविवार को केंद्र सरकार 3.0 के दूसरे पूर्ण बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की आकांक्षाओं को साकार करने वाला और देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में निर्णायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट युवा शक्ति से प्रेरित है तथा गरीब, शोषित और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति सरकार के संकल्प को मजबूती से रेखांकित करता है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह पहला बजट तीन कर्तव्यों आर्थिक वृद्धि को तेज व स्थायी बनाना, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु क्षमता निर्माण और सबका

साथ-सबका विकास से प्रेरित है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बजट का पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को गति देना और उसे बनाए रखना है। छह प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें सात रणनीतिक एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार, विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण, चैम्पियन एमएसएमई का निर्माण, अवसंरचना पर सशक्त बल, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करना तथा नगर आर्थिक क्षेत्रों का विकास शामिल है। ये सभी कदम निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन को नई दिशा देंगे। सरकार के साथ और सुधारोन्मुख प्रयासों के परिणामस्वरूप 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो समावेशी विकास की ठोस उपलब्धि है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और अवसरों के विस्तार के माध्यम से मानव पूंजी को सशक्त करने का यह बजट एक स्पष्ट और दूरगामी रोडमैप प्रस्तुत करता है, किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सभी लाभान्वित होंगे। राव ने कहा कि बजट का तीसरा कर्तव्य सबका साथ-सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो किसानों की आय बढ़ाने, दिव्यांगजन को सशक्त बनाने, मानसिक स्वास्थ्य एवं ट्रॉमा केयर तक कमजोर वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है।

कालेज प्रोफेसर्स व स्टूडेंट्स ने आम बजट को सराहा, दिए अपने सुझाव

गुरुग्राम। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 और हरियाणा के आगामी बजट पर सुझाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की मीडिया टीम की तरफ से चर्चा रखी गई। गुरुग्राम के सेक्टर-9 स्थित गवर्मेंट कालेज में हुई बजट पर चर्चा में भाजपा के पदाधिकारियों, कालेज प्रोफेसर्स और छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। यहां केंद्र द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा की गई तो हरियाणा के आगामी बजट के लिए भी सभी ने सुझाव दिए। हरियाणा भाजपा के मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी ने यहां कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट हरियाणा के विकास को नई गति देगा। बजट में आने वाले समय में इंफ्रा, कृषि और रोजगार पर बड़ा फोकस रहेगा। बजट पर चर्चा में भाजपा प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी, प्रोफेसर सुभाष सपरा, कालेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर राजेश कुंडू और प्रोफेसर मुकेश आदि ने भी अपने-अपने विचार और सुझाव रखे।

बजट में हरियाणा के हाथ खाली मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार का इंजन फेलः पंकज डावर

गुरुग्राम। कांग्रेस के गुरुग्राम जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने कहा कि देश के आम बजट में देश की राजधानी के साथ लगते हरियाणा के हाथ खाली रहने का मतलब यही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार का इंजन फेल हो चुका है। बड़ी-बड़ी बातें करने वाली हरियाणा सरकार को बजट में आईना दिखा दिया गया है। सरकार अब देश के बजट से हरियाणा को कुछ मिलने की उम्मीदें जताकर अपनी खाल बचाने का काम कर रही है। पंकज डावर ने कहा कि 12 साल से हरियाणा को देश के बजट में कुछ नहीं दिया जा रहा। विशेषकर गुरुग्राम तो पिछड़ ही रहा है। हरियाणा के साथ इसे सौतेला व्यवहार ही कहा जाएगा। सबसे छोटा राज्य होने के बाद भी सबसे अधिक राजस्व और टोल टैक्स देने वाला हरियाणा राज्य केंद्र सरकार के विकास के एजेंडे से बाहर हो चुका है। यहां के लिए रैलियों में भाजपा सरकार बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन उन्हें सिरे चढ़ाने के लिए बजट में कुछ नहीं किया जाता। इससे साफ है कि हरियाणा के साथ छलावा हो रहा है। पंकज डावर ने कहा कि हरियाणा को बजट से काफी अपेक्षाएं थीं। हरियाणा को नई रेल लाइन, उद्योगों के लिए बड़ी राहत और टैक्स में छूट जैसी कई उम्मीदें थी। प्रदेशवासियों को बजट पेश होने के साथ ही बड़ा झटका लगा है। भाजपा सरकार के दावों और यथार्थ में सिर्फ अंतर नहीं बल्कि बहुत बड़ी खाई है, जिसे कभी भरा ही नहीं जा सकता। भाजपा यहां सिर्फ वोटों की राजनीति करती है। बजट का बड़ा हिस्सा वहीं पर देती है, जहां से उनकी सरकार को सहारा मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान भी बजट से उम्मीद लगाए बैठे थे। बेरोजगार युवा भी रोजगार के लिए बड़ी योजना की बाट में थे। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्योंकि भाजपा ने हरियाणा के साथ हमेशा ही छलावा करने का काम किया है। हरियाणा से केंद्र में तीन-तीन मंत्री हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चार पीढ़ियों से मेले में लेकर आ रहे पीतल से बनी मूर्तियां

हरिभूमि न्यूज ⏭ फरीदाबाद

सूरजकुंड की वादियों में आयोजित 39 वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले में हस्तशिल्प और विरासत का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। इस वर्ष मेले में दिल्ली के प्रख्यात शिल्पकार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बालकिशन द्वारा स्टॉल नंबर 142 लगाई गई है। उनकी स्टॉल पर भगवान की अत्यंत सुंदर और सजीव मूर्तियां उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 200 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक है। वे अपनी पीतल की कलाकृतियों के साथ

पर्यटकों के बीच विशेष चर्चा का केंद्र बने हैं। दिल्ली से आए शिल्पकार बालकिशन ने बताया कि उनका परिवार पिछले चार पीढ़ियों से पीतल की मूर्तियां बनाने का कार्य कर रहा है। वे पिछले 38 वर्षों से निरंतर सूरजकुंड मेले का हिस्सा बन रहे हैं। उनकी मूर्तियों में बारीक नक्काशी और शुद्धता ही उनकी पहचान है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हमारी मूर्तियों में सिर्फ धातु नहीं, बल्कि हमारी चार पीढ़ियों का अनुभव और श्रद्धा समाहित है। सूरजकुंड मेला केवल व्यापार का मंच नहीं, बल्कि अपनी विरासत को दुनिया के सामने रखने का एक उत्सव है। बता दे कि बालकिशन को उनकी इसी असाधारण कला और समर्पण के लिए उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

गूगल प्ले स्टोर से किया जा सकता है डाउनलोड

सूरजकुंड मेला घुमाने में पर्यटकों का स्मार्ट साथी बनेगा मेला साथी ऐप

हरिभूमि न्यूज ⏭ फरीदाबाद

सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला घूमने आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से मेला साथी ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस मेला साथी ऐप के जरिए पर्यटकों को मेले से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। इससे देश-विदेशों से मेले में पहली बार अपने वाले पर्यटकों को काफी लाभ मिलेगा। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। दरअसल, सूरजकुण्ड मेले में हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। इनमें अनेक पर्यटक ऐसे होते हैं जो पहली बार मेला आते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि मेले के टिकट कितने के हैं। किस स्टॉल की क्या खासियत है। थीम स्टेट की क्या खासियत है। मेला साथी ऐप के जरिये पर्यटकों को स्टॉलों की लोकेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय, कलाकारों और शिल्पकारों का परिचय, खान-पान जोन, पार्किंग व्यवस्था, आपात सेवाएं और अन्य सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं।

सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में पर्यटकों को लुभा रहे आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स

फरीदाबाद। जिला फरीदाबाद के सूरजकुंड की हसीन वादियों में लोकल फॉर ग्लोबल-आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम के साथ आयोजित किया जा रहा 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इस बार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों के साथ-साथ भव्य और रचनात्मक सेल्फी पॉइंट्स के कारण खासा चर्चा में है। देश-विदेश से आए पर्यटक यहां न केवल पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक कलाओं और व्यंजनां का आनंद ले रहे हैं, बल्कि खूबसूरती से डिजाइन किए गए सेल्फी पॉइंट्स पर तस्वीरें खिंचवाकर यादगार पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। इस वर्ष मेले की थीम राज्यों के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश की झलक दिखाने वाले सेल्फी पॉइंट्स में उसकी ऐतिहासिक वास्तुकला, भव्य पारंपरिक द्वार और सांस्कृतिक प्रतीकों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं मेघालय की पहचान माने जाने वाले पारंपरिक हट्स को प्राकृतिक परिवेश के साथ दर्शाया गया है, जो पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। इन स्थानों पर दिनभर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है, जो परिवार और दोस्तों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर सांझा कर रहे हैं। डिजिटल तकनीक का उपयोग भी इस बार मेले की खास पहचान बना है। पिछले वर्षों की तरह, इस बार भी थीम राज्यों के डिजिटल सेल्फी बूथ लगाए गए हैं, जहां आगंतुक क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी डिजिटल तस्वीरें तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा खासकर युवा वर्ग और विदेशी पर्यटकों को खूब पसंद आ रही है, जो आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक संस्कृति का संगम देखना चाहते हैं। इसके अलावा इस वर्ष के पार्टनर कंट्री मिस्र की संस्कृति को दर्शाने वाले सेल्फी पॉइंट्स भी मेले का प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं। मिस्र की प्राचीन सभ्यता, कला और वास्तुकला से प्रेरित सजावट वाले इन पॉइंट्स पर भी लगातार भीड़ नजर आ रही है। पिरामिड और मिस्र प्रतीकों की थीम पर बने ये सेल्फी स्थल पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव दे रहे हैं। फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा सूरजकुंड मेला वर्षों से भारत की सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और लोक परंपराओं का जीवंत मंच रहा है।

कैंप का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना

शक्ति मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने सर्वोदय स्वास्थ्य चर्चा कैंप लगवाया

हरिभूमि न्यूज ⏭ फरीदाबाद

रविवार को शक्ति मार्केट वेलफेयर ऐसोसिएशन सेक्टर 7-10 द्वारा प्रधान वासुदेव अरोड़ा की अध्यक्षता में सेक्टर 10 में सर्वोदय स्वास्थ्य चर्चा कैंप लगवाया। जिसमें सर्वोदय हास्पिटल से घुटनों एवं जोड़ों में दर्द के विशेषज्ञ डॉ पंकज वलेचा डायरेक्टर एंड ऑफ हिप एंड रोबोटिक नी रिप्लेस्मेंट तथा डॉ सुमित बंसल सीनियर कंसलटेंट एंड हेड किडनी ट्रांसप्लांट एंड यूरोलॉजी उपस्थित थे।

प्रधान वासुदेव अरोड़ा ने कहा कि डॉ पंकज वलेचा व डॉ सुमित बंसल दोनों शहर के जाने माने डाक्टर हैं जो आज यहां उपस्थित लोगों को घुटनों व जोड़ो के दर्द तथा

मूत्र संबधित रोगों के लिए समाधान बतायेंगे उसके बाद जो-जो व्यक्ति कुछ पूछना चाहे उनसे पूछ सकते हैं। वशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित बेटी बचाओ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हरीश चन्द्र आजाद ने कहा कि आज वासुदेव अरोड़ा के एक आग्रह पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को इस स्वास्थ्य चर्चा का लाभ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कैंप प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं उन्होंने दोनों डाक्टरों का भी धन्यवाद किया कि वह इतनी अच्छा जानकारी हम सबको दे रहे हैं। डॉ सुमित बंसल ने बताया कि मूत्र संबधित बहुत सारी बीमारियां हम लोगों को या तो पता नहीं चलती या हम इन्हें गंभीर नहीं लेते लेकिन अगर समय पर इन बीमारियों पर ध्यान दिया जाए तो वह बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं।

स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं का गहनता से अवलोकन किया

सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार ने किया फरीदाबाद की मुख्य सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम व सफाई व्यवस्था का निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज ⏭ फरीदाबाद

मुख्यमंत्री हरियाणा के अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार ने रविवार को फरीदाबाद शहर का दौरा कर मुख्य सचटकों, ड्रेनेज सिस्टम तथा साफ-सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान उनके साथ डीसी आयुष सिन्हा, नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा तथा संयुक्त आयुक्त जितेंद्र जोशी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था, जल निकासी की स्थिति तथा स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं का गहनता से अवलोकन किया। अतिरिक्त प्रधान सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि शहर में साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए तथा कूड़ा उठान की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो। साथ ही सडक़ों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

डीसी आयुष सिंहा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान दिए गए सभी निर्देशों का शीघ्र प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

बैठक की अध्यक्षता राहुल सिंह चिंडालिया ने की

12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होगें नगि सैनिटेशन स्टाफ यूनियन के पदाधिकारी

हरिभूमि न्यूज ⏭ फरीदाबाद

आगामी 12 फरवरी 2026 की एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए नगर निगम सैनिटेशन स्टाफ यूनियन के साथियों ने नगर निगम काफ्रेंस हाल में आम सभा बुलाई। जिसमें सर्व सम्मति से हड़ताल करने लामबंद हो गए। आज की बैठक की अध्यक्षता इकाई के प्रधान राहुल सिंह चिंडालिया ने की संचालन सचिव, विशाल पारचा ने किया।

इस मौके पर विशेष रूप से संघ के जिला प्रधान दलीप बोहत एवं जिला सचिव अनिल चिंडालिया, जिला कोषाध्यक्ष रघुबीर चौटाला रहे। कर्मचारियों की सभा

को संबोधित करते हुए सैनिटेशन स्टाफ यूनियन के प्रधान राहुल सिंह चिंडालिया ने कहा कि सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। दशकों से कर्मचारी नगर निगम में अस्थाई सेवा दे रहा है, हम सरकार के 8 वायदा खिलाफी के खिलाफ हड़ताल में जाएंगे और हमारी हड़ताल कामयाब होगी। जिला सचिव अनिल चिंडालिया एवं जिला प्रधान दलीप बोहत ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की 10 ट्रेड यूनियन एक साथ 12 फरवरी की हड़ताल करेंगी। सरकार कर्मचारी विरोधी 4 श्रम संहिताएं लागू कर रही है जिसमें कर्मचारियों का शोषण है काम के घंटे बढ़ाना, यूनियन बनाने के अधिकार को छीनना यह न्यायोचित नहीं है इसलिए ये हड़ताल है सरकार 4 लेबर कोड वापस ले पुरानी पेंशन बहाल करें। निजीकरण पर रोक लगाए एवं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। हरियाणा हाई कोर्ट लगातार सरकार को पक्का न करने के लिए सरकार से सवाल पूछ रहा है सरकार सवालों से बच कर कर्मचारियों को पक्का न करने की बजाय अपील में जा रही है। सरकार के इस रवैए से कर्मचारियों में रोष है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सेवा सुरक्षा के नाम पर कर्मचारियों को 58 साल की कच्ची गारंटी दी जा रही है।

जेजेपी जिला कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन

फरीदाबाद। रविवार को जेजेपी जिला कार्यालय सेक्टर-65 में जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी द्वारा नवनियुक्त किसान प्रकोष्ठ, बीसी प्रकोष्ठ, एससी प्रकोष्ठ के हल्का अध्यक्ष का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने बताया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विचार-विमर्श कर फरीदाबाद में टीम को मजबूत करने के लिए विधानसभा के हिसाब से विभिन्न प्रकोष्ठों में हलका अध्यक्षों की नियुक्ति कर संगठन को मजबूत करने का काम किया है। नवनियुक्त सभी पदाधिकारी का स्वागत करते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि सभी साथियों की मेहनत से पार्टी को जिले में मजबूत करने का काम करेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, प्रेम सिंह धनखड़, युवा प्रभारी रंजीत ठाकुर, सुदेश ग्रोवर, अमर सिंह दलाल आदि।

पुलिस छानबीन में जुटी

नौकरी की तलाश में आए युवक ने जहरीला पदार्थ निगला, मौत

हरिभूमि न्यूज ⏭ गुरुग्राम

शिवाजी नगर थाना एरिया में नौकरी की तलाश में आए युवक ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। युवक यहां अपने चचेरे भाई के पास आया था। तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेज दिया और छानबीन शुरु कर दी है। जानकारी अनुसार, सोनीपत निवासी 24 वर्षीय विजय नौकरी की तलाश में 30 जनवरी को गुडग़ांव के ओमनगर में अपने चचेरे भाई नीरज के पास आया था। नीरज एक कंपनी में काम करता है। बताया जा रहा है कि पिछले साल दस लाख रुपए का कर्ज लेकर विजय को विदेश भेजा गया था। पिछले साल ही उसके भाई की अटैक पड़ने से मौत हो गई तो वह इंडिया आ गया। अब वह नौकरी की तलाश में गुरुग्राम आया था। शनिवार की शाम को उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबियत बिगड़ने पर उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसे मेदांता हास्पिटल पहुंचाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेज दिया और छानबीन शुरु कर दी है।

पेज एक का शेष...

पीएम मोदी के ...

कॉरिडोर, टियर-2 और टियर-3 शहरों का विकास तथा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा देने जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं।

10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। बजट में महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक इकोसिस्टम बनाने पर प्राथमिकता दी गई है। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनेंगे, जिससे शिक्षा सुलभ होगी।

कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन को प्राथमिकता बरकरार है। नारियल, काजू, कोको और चंदन उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण कदम। 'भारत विस्तार एआई' टूल किसानों को उनकी भाषा में जानकारी देगा। मत्स्य पालन और पशुपालन में उद्यमिता से गांवों में रोजगार बढ़ेगा।

विदेश मंत्रालय के ...

के चलते उन्हें सालाना आवंटित की जाने वाली बजटीय राशि में कटौती भी की गई है। जिसमें बांग्लादेश मुख्य रूप से शामिल है और उसके बजट में 50 फीसदी की कटौती की गई है। वहीं, एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि ईरान और अमेरिका के मध्य बढ़ते तनाव के बीच भारत ने इस बार चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में चाबहार परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की थी। जिसे संशोधित व्यय में करीब 400 करोड़ कर दिया गया था।

श्रीलंका, नेपाल, मालदीव का बजट बढ़ाया

मंत्रालय ने बताया कि भूटान के अलावा भारत ने जिन अन्य पड़ोसी देशों को बढ़ाकर बजट आवंटित किया है। उनमें नेपाल को 800 करोड़, मॉरीशस को 550 करोड़, श्रीलंका को 400 करोड़, अफगानिस्तान को पिछले वित्त वर्ष के 100 करोड़ की तुलना में इस बार 150 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इस नजरिए से भारत ने नेपाल के बजट में पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले इस बार 14 फीसदी, भूटान के बजट में 6 फीसदी, श्रीलंका के बजट में 33 फीसदी और मॉरीशस के बजट में करीब 10 फीसदी बढ़ोतरी की है।

म्यांमार, मालदीव का बजट में कटौती: मालदीव को भारत ने 550 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। जबकि म्यांमार के लिए नई दिल्ली ने वित्त वर्ष 2026-27 में 300 करोड़ का प्रावधान किया है। दोनों देशों के बजट में से इस बार भारत ने मालदीव के बजट में 8 फीसदी और म्यांमार के बजट में लगभग 14 फीसदी की कटौती की गई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विकास: धिकारियों के मुताबिक, भारत ने बजट की विदेशी विकास भागीदारी मद के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 6 हजार 997 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। जो मंत्रालय को दी गई कुल बजटीय धनराशि से अधिक था। यहां अहम बात ये है कि उक्त धनराशि में से 4 हजार 548 करोड़ रुपए भारत ने अपने निकट पड़ोसी देशों के लिए निर्धारित किए। जिनका इस्तेमाल कई विकास परियोजनाओं जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, घरों, सड़कों, पुलों और लघु-मध्यम स्तर की सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। बीते वर्ष भूटान के लिए संशोधित व्यय 1 हजार 950 करोड़ पर रहा। इसी क्रम में भारत ने अफगानिस्तान और वहां के आम लोगों के साथ अपने संबंधों के मद्देनजर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 150 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। पूर्व में यह धनराशि 100 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा भारत ने इस बार अपने बजट में लैटिन अमेरिकी देशों के लिए कुल 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

भूटान को 2,289, ...

और लगातार बढ़ते अत्याचारों, बांग्लादेश-पाकिस्तान के बीच बढ़ते नापाक गठजोड़ के दौर में उसे दिए जाने वाले बजट में सीधे 50 फीसदी की कटौती के साथ 60 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। मंत्रालय के बजट में इस लिहाज से देशों की दो श्रेणियां बनी हैं। एक वो जिनका बजट बढ़ाया गया है और दूसरी वो जिनके बजट में कटौती की गई है।

बजट अनुमान...

- ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी का 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- पहला कर्तव्य- आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना तथा छह हस्तक्षेपों का प्रस्ताव है

सात रणनीतिक और ...

- योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
- खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना के उद्देश्य से खनिज समृद्ध ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सहायता देने का प्रस्ताव।
- घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए कलस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर तीन समर्पित कैमिकल पार्क स्थापित करने की योजना लाई जाएगी।

वस्त्र क्षेत्र के ...

फाइबर योजना।

- मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण तथा प्रमाणन केन्द्रों के लिए पूंजी सहायता के साथ आधुनिक पारंपरिक क्लस्टरों के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना।

अवसंरचना को ठोस ....

के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और लास्ट माइल तथा दूरदराज क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाया जाएगा और पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

- संचालन को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए सी-प्लेन वी.जी.एफ. स्कीम शुरू की जाएगी।

दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चत करना

- कार्बन टैक्चर उपयोग और भंडारण (सी.सी.यू.एस.) प्रौद्योगिकियों के लिए अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा।

शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास: शहर आर्थिक क्षेत्र (सी.ई.आर.) के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए पांच हजार करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा।

पर्यावरण अनुकूल टिकाउ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए मुम्बई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बैंगलुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बैंगलुरू, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलिगुडी. के बीच सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।

वित्तीय स्थिरता, समावेश और उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय करते हुए भारत की आर्थिक वृद्धि के अगले चरण के साथ कदम-ताल मिलाते हुए बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के उद्देश्य से ''विकसित भारत के लिए बैंकिंग'' पर उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव।

पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव।

भारत की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुसार विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोक्ता अनुकूल रूपरेखा के लिए विदेश मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव।

बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्यूनिसिपल बॉण्ड जारी करने को प्रोत्साहन करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का सिंगल बॉण्ड जारी करने पर सौ करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव।

दूसरा कर्तव्य- लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमता बढ़ाना: विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम' स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव। यह फैसला भारत को वर्ष 2047 तक दस प्रतिशत की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बनाएगा।

विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग तैयार करने: संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशवरों (ए.एच.पी.) के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए ए.एच.पी. संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

अगले पांच वर्ष में एक लाख ए.एच.पी. जोड़े जाएंगे: वृद्धों की चिकित्सा और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। अगले कुछ वर्षों में डेढ़ लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

आयुष: तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे

प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने तथा अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने और पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में डब्ल्यू.एच.ओ. वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र के उन्नयन का प्रस्ताव।

पशुपालन: सरकार 20 हजार से अधिक पशु डॉक्टरों की उपलब्धता करेगी।

निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव।

ऑरेंज इकोनॉमी: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुम्बई को 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों और पांच सौ महाविद्यालयों में ए.वी.जी.सी. कंटेंट क्रिएटर लैब (सी.सी.एल.) स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव।

शिक्षा: सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरीडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने में राज्यों की सहायता करेगी।

वी.जी.एफ./पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी।

पर्यटन: मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव।

आई.आई.एम. के सहयोग से हाईब्रिड मोड में मानकीकृत, उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटन स्थलों में 10 हजार गाइडों के कौशल उन्नयन के लिए प्रायोगिक योजना शुरू की जाएगी।

सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी।

विरासत और संस्कृति पर्यटन

लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, अदिचनाल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव।

खेल: अगले दशक में खेल-कूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव।

तीसरा कर्तव्य- सबका साथ-सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसके लिए निम्नलिखित चार क्षेत्रों में लक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है:-

किसानों की आय बढ़ाना: किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पांच सौ जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, पशुपालन, उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

उच्च मूल्य कृषि: सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती समर्थन देगी जैसे:-

तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान की जाएगी।

नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव।

पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रो में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए, भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव।

भारत-विस्तार: केन्द्रीय बजट में भारत-विस्तार का प्रस्ताव, जो बहुभाषीय ए.आई. टूल है और जिसे ए.आई. प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए, आई.सी.ए.आर. पैकेज सहित एग्रीस्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए प्रतिबद्धता

उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए निमहंस-टू की स्थापना की जाएगी।

रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन किया जाएगा।

पूर्वोदय राज्यों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर ध्यान

दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई-बसों के प्रावधान का प्रस्ताव।

अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए नई योजना।

16वां वित्त आयोग: सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए।

भाग-2

प्रत्यक्ष कर

नया आय कर अधिनियम

नया आय कर अधिनियम, 2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो जाएगा।

सरलीकृत आय कर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए फॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि, आम नागरिक आसानी से उसका अनुपालन कर सके।

जीवन जीने की सुगमता: किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आय कर से छूट दी जाएगी और इस मद में स्रोत पर काटा गया कर देय नहीं होगा।

टी.सी.एस. को तार्किक बनाना: विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टी.सी.एस. दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से कम करते हुए दो प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

मानव श्रम आपूर्ति के लिए सरलीकृत टी.डी.एस. प्रावधानों से श्रम गहन कारोबारियों को लाभ होगा।

छोटे करदाताओं के लिए नई योजना का प्रस्ताव, जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से, कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण-पत्र करना संभव हो सकेगा।

करदाताओं की सुविधा के लिए डिविडेंट, निवेश से प्रपत्र 15जी अथवा प्रपत्र 15एच स्वीकार करने के लिए सिंगल विंडो।

संशोधित रिटर्न के लिए समयसीमा मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसम्बर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई।

कर रिटर्न फाइल करने के लिए अलग-अलग समय सीमा का प्रस्ताव

किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टी.डी.एस. की कटौती की जाने और टैन की आवश्यकता के बजाए निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा कराए जा सकते हैं।

छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी आय या संपत्ति की घोषणा के लिए एकमुशत छह महीने की छूट की योजना।

जुर्माने और मुकद्दमेबाजी को तार्किक रूप देना

आई.टी. आकलन और जुर्माने की कार्यवाही को सामान्य रूप से एकीकृत करने का प्रस्ताव है।

करदाताओं को अपनी पुनः आकलन कार्यवाही के बाद रिटर्न अपडेट कराने की अनुमति होगी।

आय का गलत विवरण देने पर अतिरिक्त आय कर के भुगतान के साथ छूट दी जा सकेगी।

आय कर अधिनियम के तहत मुकद्दमेबाजी की रूपरेखा को तार्किक बनाया गया है।

सहकारिता: दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार अब पशुचारे और बिनौले की आपूर्ति करने वालों तक भी किया गया है।

भारत के विकास इंजन के रूप में आई.टी. क्षेत्र को सहायता

सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आई.टी. समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सेवाएं 15.5 प्रतिशत के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के तहत आएंगी।

आई.टी. सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को तीन सौ करोड़ रुपये बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपये किया जा रहा है।

ए.पी.ए. में शामिल होने वाली कम्पनी को उपलब्ध संशोधित विवरणी की सुविधा उसकी संबद्ध संस्थाओं को भी प्रदान की जाएगी।

वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना: किसी ऐसी विदेशी कंपनी के लिए 2047 तक कर मे रियायत दी जाएगी, जो भारत से डाटा केन्द्र सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक तौर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है।

यदि, डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी संबंधित कंपनी है तो उसे लागत पर 15 प्रतिशत का सेफ हार्बर भी प्रदान किया जाएगा।

कर प्रशासन: भारतीय लेखांकन मानक में ही आय परिकलन और प्रकटन मानकों के लिए अपेक्षाएं शामिल करने के हेतू कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संयुक्त समिति गठित की जाएगी। वर्ष 2027-28 से आय परिकलन और प्रकटन मानकों पर आधारित प्रथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

अन्य कर प्रस्ताव: बायबैक के कराधान में परिवर्तन को इसलिए लाया गया कि प्रवर्तकों द्वारा बायबैक रूट का अनुचित उपयोग रोका जा सके। कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22 प्रतिशत और गैर-कॉरपोरेट के लिए 30 प्रतिशत होगा।

एल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2 प्रतिशत किया जाएगा और तेंदु पत्ते पर 5 प्रतिशत की दर को घटाकर दो प्रतिशत किया जाएगा।

वायदा सौदों पर ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों पर एसटीटी की मौजूदा 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर लगेगा।

मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है, इसलिए 01 अप्रैल, 2026 से कोई और क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15 प्रतिशत की मौजूदा मैट दर को कम करके 14 प्रतिशत किया जा रहा है।

अप्रत्यक्ष कर :

शुल्क सरलीकरण

समुद्री, चमड़ा और वस्त्र उत्पाद

निर्यात हेतु सी-फूड उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु इस्तेमाल किए गए विशेष घटकों के कर मुक्त निर्यात की सीमा को एफओबी वैल्यू के मौजूदा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जाएगा।

चमड़ा अथवा सिंथेटिक फूटवियर के निर्यात के लिए उपलब्ध कर मुक्त निर्यात, उसके विशेष उत्पादों के लिए भी अनुमत होगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र: विशेष आर्थिक क्षेत्रों से लेकर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में पात्र विनिर्माण संयंत्रों द्वारा विक्रय की सुविधा हेतु एक विशेष एकबारगी उपाए का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए रियायती दरों का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे विक्रय की मात्रा उनके निर्यात के निर्धारित अनुपात तक सीमित होगी।

जीवन की सुगमता:

व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात की जाने वाली सभी कर योग्य सामग्रियों पर टैरिफ दर को 20 प्रतिशत के घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा।

सीमा-शुल्क सरलीकरण प्रक्रिया

वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचालन में कम से कम हस्तक्षेप

विश्वास आधारित प्रणालियां

एईओ के रूप में परिचित टियर 2 और टियर 3 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। पात्र विनिर्माणकर्ता और आयातकों के लिए भी समान शुल्क स्थगन सुविधा का प्रस्ताव।

सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया।

कार्गो के समाशोधन के लिए अधिमान्य व्यवहार हेतु एईओ प्रमाणन का लाभ लेने के लिए सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सीमा-शुल्क भंडारण,ऱ स्व-प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा-परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा।

व्यापर सुगमता

विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो समाशोधन के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े डिजिटल विंडो के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा।

खाद्य, औषधि, पौध, पशु और अन्य वन्य जीव उत्पादों, जो निषिद्ध कार्गो का 70 प्रतिशत होता है, के समाशोधन शामिल प्रक्रियाओं को अप्रैल 2026 तक संचालन रूप दिया जाएगा।

जिन वस्तुओं के लिए कोई अनुपालन आवश्यकता नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद समाशोधित किया जाएगा।

सभी सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा-शुल्क एकीकृत प्रणाली 2 वर्षों में शुरु की जाएगी।

गैर-सन्निविष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखिम आकलन हेतु एआई प्रौद्योगिकी उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में कंटेनर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

निर्यात के नए अवसर

विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा बीच समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी पत्तन पर ऐसी मछली के उतराई को निर्यात वस्तु के रूप में माना जाएगा।

ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार में पहुंच के लिए भारत के छोटे व्यवसाय, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुरियर निर्यात प्रति खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरफ से हटाया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी से जुड़े प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी।

सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का समाधान चाहने वाले ईमानदर करदाता अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद कर सकेंगे।

ऑपरेशन सिंदूर के ....

वायुसेना के लिए की जाने वाली 114 बहुआयामी लड़ाकू विमानों (एमआरएफए) की खरीद प्रक्रिया जोर पकड़ेगी। राफेल लड़ाकू विमान इसके केंद्र में है।

मजबूत होगा सुरक्षा घेरा: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार और वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया यह शानदार बजट देश की सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। वित्त मंत्री ने पहले के मुकाबले 15 फीसदी से भी अधिक, 7.85 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट का आवंटन किया है।

तीन कर्तव्यों से प्रेरित बजट

उन्होंने कहा, ये बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित, आर्थिक विकास को गति देने, उसे सतत बनाए रखने, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और सभी की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। इससे सभी प्राथमिकताएं मिलकर समावेशी विकास को गति देंगी, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देंगी और टिकाऊ अवसंरचना का निर्माण करेंगी। बजट को इस तरह से तैयार किया गया है कि जिससे विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। जिसमें गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

रक्षा की चार मदों में इतना आवंटन

1 पूंजीगत खरीद- 2.19 लाख करोड़ (पहले के 1.80 लाख की तुलना में 21.84% की वृद्धि)।

2 राजस्व मद- 3.65 लाख करोड़ प्लस (पहले के 3.11 लाख करोड़ की तुलना में 17.24% की वृद्धि)।

3 रक्षा पेंशन- 1.71 लाख करोड़ प्लस (पहले के 1.60 लाख करोड़ की तुलना में 6.53% की वृद्धि)।

4 मंत्रालय (सिविल)- 28554.61 करोड़ (पहले के 28682.97 करोड़ के साथ -0.45% की मामूली कमी)। मंत्रालय ने बताया ने रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटित बजट में से पूंजीगत खरीद के लिए 27.95 फीसदी, राजस्व के लिए 26.40 फीसदी, रक्षा पेंशन के लिए 21.84 फीसदी और असैन्य संगठन के लिए 3.64 फीसदी धनराशि आवंटित की गई है।

चुनौतियों में मजबूत होगी सामरिक क्षमता

जानकारों का कहना है कि विश्व में जारी कई युद्धों, सैन्य संघर्षों के साथ ही चीन और पाकिस्तान की सीमा से भारत के लिए बढ़ते सुरक्षा खतरे का पूरी मुस्तैदी के साथ मुकाबला करने के लिए रक्षा बजट में की गई यह बढ़ोतरी बिल्कुल वाजिब है। वहीं, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच सेनाओं के आधुनिकीकरण को रफ्तार देने के लिए बजट में इस बढ़ोतरी की दरकार थी। 2025-26 की तीसरी तिमाही, दिसंबर तक मंत्रालय ने कुल 2.10 लाख करोड़ के समझौते किए हैं। आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) वाले प्रस्ताव 3.50 लाख करोड़ के रहे। पूंजीगत खरीद से जुड़ी अन्य परियोजनाओं में अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान, स्मार्ट-लीथल वेपन, जहाज, पनडुब्बी, यूएवी, ड्रोन सहित विशेष वाहन मुख्य हैं। बढ़े हुए बजट के जरिए सरकार ने सैन्य बलों और उनकी क्षमताओं को विश्व के सर्वोच्च मानकों के हिसाब से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

रक्षा पेंशन, पूर्व सैनिकों के कल्याण पर जोर

रक्षा बजट में मौजूदा और पूर्व सैन्यकर्मियों की पेंशन के लिए 1 लाख 71 हजार 338.22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो पहले के मुकाबले की गई 6.56 फीसदी की बढ़ोतरी है। इस धनराशि की मदद से कुल करीब 34 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को स्पर्श और पेंशन वितरण के अन्य माध्यमों के जरिए संबंधित विभाग अपनी कार्रवाई को अमलीजामा पहनाएंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों, आश्रितों के कल्याण के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान के लिए रक्षा बजट में एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के तहत 12 हजार 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जो पूर्व से 45.49 फीसदी अधिक है और इससे सरकार ने बीते 5 सालों में ईसीएचएस के फंड में 300 फीसदी से अधिक की वृद्धि की है।

डीआरडीओ को 29 ...

किया गया है।

बीआरओ को मिले 7394 करोड़: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय को आवंटित किए गए 7.85 लाख करोड़ के कुल बजट में से देश की सीमाओं के विकास के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आवंटन में वृद्धि करते हुए इसे 7 हजार 394 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में यह 7 हजार 146.50 करोड़ रुपए था। बजट में की गई बढ़ोतरी की मदद से कई सामरिक परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। जिसमें सुरंगें, पुल, हवाई पट्टियां मुख्य रूप से शामिल हैं। जिससे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन के साथ ही सीमा से लगे इलाकों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी भी स्थापित की जा सकेगी।

यूं आत्मनिर्भरता को लगेंगे पंख: मंत्रालय के मुताबिक, चुनौतीपूर्ण समय में वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों और विदेशी विक्रेताओं के साथ बनी हुई घरेलू जरूरतों के मद्देनजर सेनाओं के भावी आधुनिकीकरण के लिए आयात के विकल्प की तलाश के साथ-साथ स्वदेशीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

सैन्य प्लेटफार्म की आसानी से होगी देखरेख

रक्षा बजट में राजस्व मद में वित्त मंत्री ने 3 लाख 65 हजार 478.98 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जो बीते वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले 17.24 फीसदी अधिक है। 1 लाख 58 हजार 296.98 करोड़ की धनराशि ऑपरेशन और अन्य खर्चों की पूर्ति जैसे वेतन और भत्तों के लिए रखी गई है।

ये कॉरिडोर हैं:...

आईटी हब्स को जोड़ेगा।

रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन कॉरिडोर से यात्रा समय में भारी कमी आएगी। उन्होंने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए करीब 1.20 लाख करोड़ अलग से आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्षों के निवेश से रेल दुर्घटनाएं लगभग 95% कम हुई हैं। अब ट्रैक, लोकोमोटिव, वैगन और कोच मेंटेनेंस, कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम की तेजी से स्थापना, सीसीटीवी कैमरे, ओएचई सिस्टम अपग्रेडेशन, स्टेशन पुनर्विकास और यात्री सुविधाओं पर फोकस बढ़ेगा।

प्रोपल्शन सिस्टम में आत्मनिर्भरता

मंत्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रोपल्शन सिस्टम है। भारत में डिजाइन और निर्मित प्रोपल्शन सिस्टम अब अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे शीर्ष देशों को निर्यात हो रहे हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड उपलब्धियां

35,000 किमी नई ट्रैक निर्माण

47,000 किमी इलेक्ट्रिफिकेशन

ब्रॉड-गेज नेटवर्क का 99.5% से अधिक इलेक्ट्रिफाइड

वंदे भारत स्लीपर और चेयर कार ट्रेन, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनों का निर्माण और वैगनों की रिकॉर्ड इंडक्शन अभूतपूर्व गति से चल रहा है।

स्थिरता पर जोर

रेल परिवहन सड़क परिवहन से लगभग 95% कम प्रदूषण करता है। यह प्रधानमंत्री के ग्रीन मास ट्रांसपोर्ट विजन से जुड़ा है।

यह रिकॉर्ड आवंटन भारतीय रेलवे को राष्ट्रीय विकास, आर्थिक वृद्धि और समावेशी कनेक्टिविटी की रीढ़ बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। विकसित भारत@2047 के संकल्प के अनुरूप तेज कनेक्टिविटी, कुशल लॉजिस्टिक्स और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित होगा।

कृषि बजट 1.32...

बजट बताया है।

पंचायतों को दोगुनी सीधी सहायता, विकसित और स्वावलंबी ग्राम की दिशा में बड़ा कदम

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग के ताज़ा निर्णय के अनुसार पंचायतों को सीधे 55,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जाएगी। उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि पहले पाँच वर्षों में पंचायतों को कुल लगभग 2,36,000 करोड़ रुपये सीधे मिले थे, जो अब बढ़कर 4,35,000 करोड़ रुपये हो गए हैं– यानी लगभग दोगुना। चौहान ने विश्वास जताया कि 'विकसित भारत जी राम जी' की 1,51,000 करोड़ रु. की राशि और वित्त आयोग के तहत मिलने वाले 55,900 करोड़ रु. मिलकर विकसित ग्राम, स्वावलंबी ग्राम, रोजगारयुक्त और गरीबीमुक्त गांव के निर्माण में अभूतपूर्व भूमिका निभाएँगे।

कृषि बजट में उल्लेखनीय वृद्धि, अनुसंधान और सस्ती खाद पर विशेष ज़ोर

कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विभाग का बजट बढ़ाकर इस वर्ष 1,32,561 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान, विशेषकर आईसीएआर सहित, के लिए 9,967 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शोध और नवाचार को बल मिलेगा। किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी पर उन्होंने कहा कि सस्ता खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 1,70,944 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है, ताकि उत्पादन की लागत कम हो और किसान को राहत मिले।

नेशनल फाइबर स्कीम और मेडिसिनल प्लांट्स से किसानों को सीधा लाभ

चौहान ने कहा कि नेशनल फाइबर स्कीम के अंतर्गत सिल्क, वूल और जूट जैसे फाइबर पर फोकस किया गया है, जिससे इनसे जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।उन्होंने यह भी कहा कि आयुष मंत्रालय में मेडिसिनल प्लांट्स के सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट से संबंधित प्रावधानों का फायदा औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा।

लखपति दीदी और...

आजीविका तक सीमित न रहकर उद्यमी के रूप में आगे बढ़ सकेंगी, यही इस पहल का उद्देश्य है।

ग्रामीण विकास बजट....

प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के कुल बजट में अकेले 'विकसित भारत जी राम जी' योजना के लिए राज्यों के अंशदान सहित लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।

विकसित भारत का रोडमैप है केंद्रीय बजट

एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड़ के प्रावधान से हरियाणा को बड़ा फायदा होगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट दरअसल विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का दूरदर्शी और ऐतिहासिक रोडमैप भी है। अंत्योदय की भावना से प्रेरित इस बजट के तीन स्पष्ट विजन हैं। रफ्तार, क्षमता और सबका साथ। रफ्तार यानि उत्पादकता बढ़ा कर आर्थिक विकास की गति तेज करना। क्षमता यानि देश की प्रगति में भागीदारी के लिए लोगों की प्रतिभा और क्षमता निखारना। 'सबका साथ, सबका विकास' प्रधानमंत्री का सुशासन का मूल मंत्र है, जिसका अर्थ है हर किसी के पास कमाई के पर्याप्त अवसर और संसाधन हों। इसलिए तात्कालिक लोकप्रियता की आकांक्षा से मुक्त नया बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का दस्तावेज है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान से स्पष्ट है कि भारत का इरादा आयात घटाने से आगे निर्यात बढ़ाने का है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रहना उसकी मजबूती को ही दर्शाता है। ऐसे समय जबकि तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिचकोल खा रही हैं, भारत की विकास दर सात प्रतिशत रहना मोदी सरकार की बेहतर आर्थिक नीतयों और वित्तीय अनुशासन का भी परिणाम है। ऊर्जा सुरक्षा भविष्य की प्रगति की कुंजी बननेवाली है। इसलिए उस पर भी फोकस रहेगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में साढ़े 12 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और सिटी इकॉनोमिक रीजन का विकास खासकर हरियाणा जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर केंद्रित औद्योगिक राज्य की प्रगति को नयी उड़ान देगा। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से भी लाभार्थी राज्यों में हरियाणा अग्रणी रहेगा। सेमीकंडक्टर हब के लिए 40 हजार करोड़ रुपये और बायोफार्मा सेक्टर पर फोकस भारत को प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनायेगा, तो दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, देश में बड़े टैक्सटाईल पार्क और पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने से इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा।

बजट में खास

- कॉरपोरेट कर में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) घटाकर 14%
- होटल में रहने व ठहरने पर टीडीएस अब कुल व्यय राशि का सिर्फ 2%
- भूमि अधिग्रहण से प्राप्त आय पर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को विशिष्ट छूट प्रदान की जाएगी
- वायुसेना के आयातित इंजनों सहित एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट के पार्टों पर सीमा शुल्क शून्य किया
- चबाने वाला तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू कर 25% से बढ़कर 60%
- मिश्रित कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) में प्रयुक्त बायोगैस/कम्प्रेस्ड बायोगैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट
- क्रिप्टो करंसी के संबंध में गलत विवरण देने पर अर्थदंड प्रतिदिन 200 रुपए, विवरण ठीक न करने पर 50,000
- रिटर्न अपडेट में एक्स्ट्रा आय बताने पर दंड नहीं लगाए जाने का प्रस्ताव

विवरण प्रस्तुत करने में भूल पर 7 साल के बजाए 2 वर्ष की सजा

- वित्तीय लेन-देन या रिपोर्ट किए जाने योग्य खाते के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक के लिए अर्थदंड को अधिकतम सीमा के अधीन चूक के प्रत्येक दिन के लिए प्रभारित शुल्क में बदलने का प्रस्ताव है।
- लेखा और दस्तावेज प्रस्तुत करने, और नकद में किए गए भुगतान के लिए कटौतीकर्ता से टीडीएस का भुगतान सुनिश्चित करने की अपेक्षा को पूरी तरह अपराध से बाहर करने का प्रस्ताव है।
- सभी अभियोजनों को युक्तिसंगत करते हुए सश्रम कारावास से बदल कर साधारण कारावास किया जाएगा।
- किसी अपराध (बार-बार के अपराध को छोड़कर) के लिए अधिकतम अधिकतम दंड को 7 वर्ष से कम करके 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- ऐसे मामलों में जहां वर्तमान में अधिकतम दंड दो वर्ष है, वहां दंड को जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना तथा न्यूनतम कारावास की सीमा से रहित करते हुए कम करके 06 माह कर दिया गया है।
- यह भी प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम 2025 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन बचाई गई कर की राशि के आधार पर होगा और दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में होगा। ऐसे मामलों में कारावास के अधिकतम दंड की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है और अनिवार्य जुर्माने की अपेक्षा को शिथिल करके वैकल्पिक बना दिया गया है।
- यह भी प्रस्ताव है कि गौण अपराध के लिए दंड के रूप में केवल जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।

इनकम टैक्स स्लैब जस के तस, थोड़ी फीस से 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न

आम आदमी छात्र और बुजुर्गों को वित्त मंत्री ने दिए ये खास तोहफे

नई और पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं

आम बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई और पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की आय ही आयकर से मुक्त रहेगी। हालांकि, आयकर अधिनियम के सेक्शन 87ए के तहत आप 5 लाख तक की आय पर कर बचा सकते हैं। वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 4 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं देना होगा। इसमें आयकर अधिनियम के सेक्शन 87ए के तहत वेतन प्राप्त करने वालों को 12.75 लाख रुपए तक की आय पर और अन्य 12 लाख तक की आय पर कर छूट पा सकते हैं।

टैक्स को लेकर ये बड़े बदलाव

- **1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून:** केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, इसके जरिए सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी।
- **विदेश यात्रा करना हुआ सस्ता:** बजट में आम आदमी का विदेश घूमना हुआ सस्ता विदेश यात्रा करने वालों के लिए ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस अब सिर्फ 2% होगा, जो पहले 5% और कुछ मामलों में 20% तक था। इससे घूमने-फिरने का खर्च तुरंत बढ़ने से बचेगा।
- **31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे रिवाइज्ड रिटर्न** इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में सुधार करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब मामूली फीस देकर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा।

इन चीजों को समझिए

पुरानी में 2.5 लाख और नए में 12 लाख रुपए तक की आयकर छूट

सवाल 1: पुरानी और नई टैक्स रिजीम में क्या अंतर है?
जवाब: नए टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए तक की कमाई आय कर मुक्त रहती है, लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन नहीं मिलते हैं। वहीं, अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।
सवाल 2: पुरानी टैक्स रिजीम में किस तरह की छूट मिलती है?
जवाब: अगर आप ईपीएफ, पीपीएफ और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश करते हैं। तो आपकी कुल कर योग्य आय में से ये आय कम हो जाएगी। वहीं, मेडिकल पॉलिसी पर किए गए खर्च, होम लोन पर चुकाए गए ब्याज और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किए गए रुपए भी आपकी कर योग्य आय से घट जाते हैं।
सवाल 3: पुरानी टैक्स रिजीम किन लोगों के लिए बेहतर है?
जवाब: अगर आप निवेश और टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं, तो पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। वहीं अगर आप कम टैक्स रेट और टैक्स डिडक्शन के झंझटों से बचना चाहते हैं तो नई टैक्स रिजीम आपके लिए सही हो सकती है।

टीडीएस के लिए अब आवेदन नहीं

- **टीडीएस न कटवाने के लिए आवेदन की जरूरत नहीं:** टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) नहीं कटवाने के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। नियमों के अनुसार अब अगर आप पर इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अभी इसके लिए फॉर्म 15जी (60 साल से कम वालों के लिए) या फॉर्म 15एच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) जमा करना होता था।
- **फ्यूचर-ऑप्शंस ट्रेडिंग करना महंगा:** सरकार ने फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। ऑप्शंस पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% किया गया है। इसे ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा।

छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए आसान मौका

- विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों और उनके परिवारों के लिए बजट राहत लेकर आया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्चों के लिए भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 5% होता था। इससे छात्रों पर शुरुआती वित्तीय बोझ कम होगा, एजुकेशन लोन पर निर्भरता घटेगी और इंपोर्टेड स्टडी मटेरियल या पार्सल की क्लियरेंस भी तेज होगी।

टीडीएस की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड

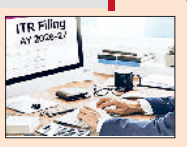

- छोटे करदाताओं के लिए लोअर या निल टीडीएस सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी। अब अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म की गई है। वहीं 7 और दुर्लभ बीमारियों के इलाज से जुड़े दवाइयों और विशेष भोजन को भी ड्यूटी-फ्री किया गया है। यह छूट बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026-25 में इनकम टैक्स को लेकर किसी तरह की राहत नहीं दी है। बजट में इनकम टैक्स को लेकर को कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई है। वहीं, विदेश रुपए भेजने पर अब 5% के बदले 2% टैक्स लगेगा। कर विशेषज्ञों के अनुसार सरकार ने पिछले बजट में ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स छूट को 7 लाख बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया था। ऐसे में इस साल बदलाव होने की संभावना न के बराबर ही थी। हालांकि, बजट 2026 में आम आदमी, मध्यमवर्गीय परिवारों, छात्रों और बुजुर्गों के लिए कई अहम राहत भरे कदम उठाए गए हैं। बजट में इन पर टैक्स का बोझ कम, आसान नियम और सुरक्षित, बचत के लिए नियम लाए हैं। सरकार ने इसे 'परिवारों की समृद्धि से राष्ट्र की मजबूती' के लक्ष्य से जोड़ा है। अब विदेश से यात्रा के दौरान एक लैपटॉप को पर्सनल सामान के साथ लाने पर स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए कस्टम डिक्लेरेशन और ड्यूटी पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिससे एयरपोर्ट पर लगने वाला समय और तनाव दोनों कम होंगे।

अत्यधिक सट्टेबाजी रोकने के लिए वित्त मंत्री ने सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाया

शेयर बाजार के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एसटीटी बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया

निफ्टी 25500 के नीचे गया और बाद में 25800 के ऊपर क्लोज हुआ

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान जैसे ही शेयर बाजार के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एसटीटी टैक्स को बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद ही मार्केट में गिरावट हावी हो गई। इंट्रा में निफ्टी 25500 के नीचे चला गया और उतार-चढ़ाव के बाद 25800 के ऊपर क्लोज हुआ। वित्त मंत्री ने बताया कि एसटीटी में बढ़ोतरी मामूली है और इसका एकमात्र उद्देश्य अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसटीटी में वृद्धि केवल वायदा और विकल्प सौदों पर ही लागू होगी, क्योंकि इनमें अत्यधिक सट्टेबाजी और जोखिम शामिल है।

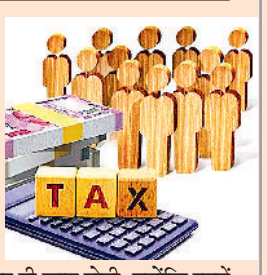

क्या होता है एसटीटी?

एसटीटी (सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स) एक प्रकार का टैक्स है जो शेयर बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री पर लगता है। शेयर, डेरिवेटिव्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदते या बेचते समय यह टैक्स लागू होता है। इस टैक्स को सरकार ने साल 2004 में शुरू किया था ताकि शेयर बाजार में सट्टेबाजी कम हो और सरकार को टैक्स से कमाई हो सके। फ्यूचर सेगमेंट में एसटीटी को पहले के 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। वहीं, ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है, जो कि पहले 0.10 फीसदी था।

करों से 44,04,086 करोड़ की आय

वर्ष 2026-27 में सरकार को टैक्स से कुल 44,04,086 करोड़ की आय होने का अनुमान है। इसमें इनकम टैक्स से 14,66,000 करोड़, कंपनियों पर लगने वाले टैक्स से 12,31,000 करोड़, जीएसटी से 10,19,020 करोड़, एक्साइज ड्यूटी से 3,88,910 करोड़ और कस्टम ड्यूटी से 2,71,200 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि जीडीपी की तुलना में टैक्स रेवेन्यू घटने की आशंका है। 2026-27 में 11.2% रहने का अनुमान है।

लागत कम कर उत्पादन बढ़ाने पर जोर

नवकरणीय और नाभिकीय उर्जा विमान के इंजन, पुर्जों पर 0 टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनपुट लागत कम करने, घरेलू विनिर्माण पर बल देने तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित मदों पर सीमा-शुल्क ड्यूटी कम किए जाने का प्रस्ताव रखा है। महत्वपूर्ण खनिज मोनाजाइट पर मूल सीमा शुल्क ड्यूटी की दर 2.5% से घटाकर शून्य कर दी गई है। एअरक्रॉफ्टों और एअरक्रॉफ्टों के विनिर्माण के लिए एअरक्रॉफ्ट के इंजनों सहित उसके घटक या पार्ट पर सीमा शुल्क पूरी तरह से शून्य किए जाने का प्रस्ताव है।

सौर ग्लास पर सीमा शुल्क शून्य

नवकरणीय ऊर्जा के तहत सौर ग्लास के विनिर्माण में उपयोग हेतु सोडियम एंटीमोनेट 7.5% से कम करके शून्य, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की बैटरियों के लिए लिथियम ऑयन सेलों के विनिर्माण में उपयोग हेतु वस्तुएं शून्य कर पर उपलब्ध होंगी। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित वस्तुएं पर सीमा शुल्क इयटी शून्य कर दी गई है।

आम बजट पर विशेषज्ञों का नजरिया

शिक्षा पर समग्र दृष्टिकोण, तकनीकी कौशल के साथ युवाओं को रोजगार

डॉ. भूपेंद्र सुल्लेरे
शिक्षाविद
भोपाल

केंद्रीय बजट में शिक्षा को मानव पूंजी का मूल आधार मानते हुए स्कूली, तकनीकी और उच्च शिक्षा दोनों में निवेश और सुधार पर बल दिया गया है। बजट में सरकारी स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब तथा डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे कदमों से सीखने की गुणवत्ता और तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवा आधुनिक रोजगार के अवसरों के लिए तैयार होंगे। साथ ही, हर जिले में लड़कियों के होस्टल और नए डिज़ाइन/ क्रिएटिव संस्थान जैसे उच्च शिक्षा संवर्धन प्रस्ताव हैं, जो लिंग समानता और समावेशी शिक्षा को मजबूत करेंगे। बजट में नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप, उन्नत तकनीकी पाठ्यक्रम, शोध-उन्मुख केंद्रों और विद्यालय-विश्वविद्यालय लिंकिंग को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है, जिससे भारत वैश्विक शिक्षा-केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एजुकेशन टू इम्प्लॉयमेंट कमेटी जैसे संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव रखा है, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच पुल मजबूत होगा।

स्थिर नीति, संतुलित आर्थिक संकेत और राजकोषीय अनुशासन से विश्वास बढ़ा

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक
आईआईएम, इंदौर

केंद्रीय बजट 2026 की एक उल्लेखनीय विशेषता इसकी नीतिगत स्थिरता और पूर्वानुमेय आर्थिक दिशा है। सरकार ने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विकास को कर्ज-आधारित विस्तार के बजाए संतुलित संसाधन प्रबंधन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। यह दृष्टिकोण सार्वजनिक वित्त की विश्वसनीयता को मजबूत करता है और दीर्घकालिक आर्थिक योजना के लिए आवश्यक आधार तैयार करता है। पूंजीगत व्यय को रूपए 12.2 लाख करोड़ तक बनाए रखना यह दर्शाता है कि सरकार अल्पकालिक लोकप्रिय निर्णयों के बजाय आर्थिक क्षमता के निर्माण पर ध्यान दे रही है। बेहतर अवसंरचना और स्थिर नीतिगत माहौल का प्रत्यक्ष लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिल सकता है, जो कम लागत, बेहतर संपर्कऔर अधिक भरोसेमंद मांग वातावरण में विस्तार करने में सक्षम होंगे। नीति निरंतरता से इन उद्यमों के लिए निवेश और उत्पादन संबंधी निर्णय लेना सरल होता है। इस व्यापक आर्थिक ढांचे में शिक्षा को एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा के लिए 1.28 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन दर्शाता है कि सरकार मानव पूंजी में प्राथमिकता दे रही है।

हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, मेडिकल में बढ़ी सुविधा तीन आयुर्वेदिक एम्स, पांच चिकित्सकीय पर्यटन केन्द्र

बजट 2026-27 में शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें 55,727 लाख करोड़ रुपये उच्च शिक्षा विभाग और 83,562 लाख करोड़ रुपये स्कूल और साक्षरता विभाग के लिए हैं। इस बार शिक्षा के लिए आवंटित बजट पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 फीसदी अधिक रहा। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए बजटीय प्रावधान करते हुए भविष्य की तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौशल विकास और मेडिकल शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। साथ ही, देश के हर जिले में महिला छात्रावास खोलने की भी घोषणा की गई है। बजट में टियर-2 और टियर-3 कस्बों में कॉर्पोरेट मित्र बनाने की भी घोषणा की गई है, जिससे पेशेवर संस्थानों को सुविधा और प्रशिक्षण मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

शिक्षा बजट 8.27% बढ़कर हुआ 1.39 लाख करोड़ रुपये

पिछले वर्ष से 8.27% अधिक आवंटन

2026-27 के लिए शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं 2025-26 के बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल 1,28,650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

दवा उत्पादन के लिए दस हजार करोड़ किए जाएंगे खर्च

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत के दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए अगले 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में हम दुर्लभ दवाओं के लिए विदेशों पर निर्भर है लेकिन इस पहल से अब भारत में ही आधुनिक दवाओं का निर्माण होगा और भारत दुनिया को दवाई सप्लाई कर सकेगा। देश में ऐसे पहले से ही 7 संस्थान मौजूद हैं और इन्हें भी आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। जिला अस्पताल आधुनिक तकनीक से लैस होंगे तथा इमरजेंसी वार्ड की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी।

क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा

वित्त मंत्री ने दवाओं के साथ उसके विशेषज्ञों की भी जरूरत पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पूरे देश में 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके जरिए थेरेपी और दवाओं की जांच जल्दी से हो जाएगी। ऐसे में देश में तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोले जाने की घोषणा हुई है।

स्कूलों व कॉलेजों में 'कन्टेंट क्रिएटर लैब' बनेंगी

सरकार ने माना है कि भविष्य 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'डिजिटल कंटेंट' का है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कन्टेंट क्रिएटर लैब' बनाने का फैसला लिया गया है। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 'एआई एप्लीकेशन' पर आधारित विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जिससे देश की युवा शक्ति डिजिटल युग के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।

गर्ल्स हॉस्टल और जिला अस्पतालों का कायाकल्प

महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में एक 'गर्ल्स हॉस्टल' बनाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला अस्पतालों की क्षमता में 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। लघु उद्योगों की मदद के लिए सरकार एक अनूठी योजना लेकर आई। सीए, सीएस और सीएमए जैसे संस्थान अब शॉर्ट टर्म कोर्स तैयार करेंगे, जिससे देश में 'कॉर्पोरेट मित्र' तैयार होंगे। ये एक्सपर्ट्स विशेष रूप से छोटे शहरों के व्यापारियों और उद्योगों को प्रोफेशनल मदद देंगे। आईआईएम की मदद से 10 हजार टूरिस्ट गाइड्स तैयार किए जाएंगे।

बेटियों की पढ़ाई में अब नहीं आएगी कोई रुकावट

अक्सर देखा जाता है कि गांव या छोटे शहर की लड़कियों को बड़े कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन वहां रहने का इंतजाम करना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। बजट में लिया गया यह फैसला लड़कियों को कॉलेज तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगा। जब हर जिले में अपना एक हॉस्टल होगा, तो मां-बाप भी बिना किसी डर के अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भेज सकेंगे। इससे न केवल पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कम होगी, बल्कि लड़कियां खुद को ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगी। यह कदम महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की तरह देखा जा रहा है।

7 दवाओं से कस्टम ड्यूटी खत्म

सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा, कई दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत के दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए अगले 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में हम दुर्लभ दवाओं के लिए विदेशों पर निर्भर है लेकिन इस पहल से अब भारत में ही आधुनिक दवाओं का निर्माण होगा और भारत दुनिया को दवाई सप्लाई कर सकेगा। देश में ऐसे पहले से ही 7 संस्थान मौजूद हैं और इन्हें भी आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।

बजट में खास

शिक्षा के क्षेत्र को सौगात

- 01 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
- 05 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापना की घोषणा
- 04 टेलीस्कोप/खगोल विज्ञान सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी
- 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना
- 15000 माध्य. स्कूलों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना
- डिजिटल नॉलेज ग्रिड खोले जाएंगे
- हर जिले में छात्राओं के लिए होगी गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना

स्वास्थ्य क्षेत्र में ये नए संस्थान खोलने की घोषणा

- 05 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापना की घोषणा
- 02 नए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान खुलेंगे
- 03 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनेंगे
- 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म
- 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा
- 07 नए आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव
- 07 पहले से मौजूद संस्थान होंगे अपडेट
- 17 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी खत्म
- कैंसर व शुगर की दवाइयां होंगी सस्ती
- एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के नए संस्थान बनेंगे
- वेटनरी और पैरा-वेट कॉलेज/अस्पताल की स्थापना

युवाओं पर फोकस

युवाओं के सपनों को पांव रफ्तार से दौड़ेगा देश

सरकार ने आम बजट में सबसे बड़ी धुरी 'युवा शक्ति' और 'आधुनिक तकनीक' को बनाया है। सरकार ने इस बजट के जरिए न केवल शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की है, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बायो-फार्मा और एआई जैसे उभरते क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार युवाओं को 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बनाना चाहती है। बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए भी विशेष रोडमैप तैयार किया गया है जो रोजगार व व्यापार में सहायक बनेंगे। बायो-फार्मा व एआई क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

बायो-फार्मा और मेडिकल सेक्टर में आएगी क्रांति

सरकार ने भारत को दुनिया का मेडिकल हब बनाने के लिए सरकार ने 'बायो फार्मा शक्ति' योजना का ऐलान किया है। अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च खुलेंगे। वहीं 7 पुराने संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, पशुपालन के क्षेत्र में भी 20 हजार नए वेटरनरी प्रोफेशनल तैयार करने के लिए विशेष कॉलेज खोले जाएंगे।

बुजुर्गों को रेल यात्रा में नहीं मिली छूट बाकी सब यथावत

भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के बाद से बुजुर्गों को सफर में मिलने वाली रियायत खत्म कर दी थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वित्त मंत्री अपने पिटारे से यह तोहफा जरूर देंगी लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की घोषणा इस बजट में नहीं की गई जिससे बुजुर्गों को निराशा हाथ लगी। वहीं बुजुर्गों के लिए इनकम टैक्स की मौजूदा छूट सीमा भी पूर्व जैसे ही यानी 60 से 79 साल की उम्र वालों के लिए टैक्स छूट 3 लाख रुपये और 80 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपये ही रहेगी।

महिलाओं को मिला शी-मार्ट का तोहफा

- ग्रामीण महिलाओं के लिए स्व-स्हायता उपक्रम शी-मार्ट का ऐलान
- भारत- विस्तार एआई टूल्स से कृषि उत्पादन में होगी सहायता
- पीएम दिव्यांशा केंद्रों को बनाया जाएगा मजबूत

रोजगार के क्षेत्र में घोषणा

- 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' योजना
- खादी हथकरघा क्षेत्र को दिया जाएगा बढ़ावा
- निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को मजबूती देने का लक्ष्य

केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए एक नई पहल शी-मार्ट की घोषणा की है। यह योजना महिलाओं के व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है। ताकि महिलाओं को और अधिक आर्थिक अवसर मिल सकें। शी-मार्ट्स समुदाय-संचालित रिटेल आउटलेट होंगे जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं खुद का कारोबार चला सकेंगी।

महिलाओं की वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपए हो

वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की वह महिला सदस्य होती है जिसकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम एक लाख रुपये हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, अब तक दो करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और लक्ष्य 2027 तक तीन करोड़ महिला एसएचजी सदस्यों की वार्षिक आय को एक लाख रुपये तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उधार पर निर्भर रहकर काम करने की बजाय स्वयं के व्यवसाय की मालिक बनने में सहायता देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता (लोन) भी उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि वे अपने व्यापार को मजबूत कर सकें। बजट 2026 में महिलाओं के लिए यह नई पहल उनके आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमिता और स्वयं-का व्यवसाय चलाने वाली क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कदम है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के लिए 'उद्यमों के मालिक' बनने की दिशा में "अगला कदम" बताया।

आम बजट पर आम नजरिया

पहला बजट जो एआई और आईटी को समर्पित

बजट एआई और आईटी को भारत के भविष्य के विकास की प्रमुख शक्ति के रूप में रेखांकित करता है। एआई समेत उभरती तकनीकों के रोजगार पर प्रभाव और कौशल आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए एक विशेष समिति के गठन का सुझाव दिया गया है, जो कौशल विकास और रोजगार तैयारियों को दिशा देगी। सरकारी सेवाओं में एआई आधारित समाधानों के उपयोग, डिजिटल अवसंरचना के विस्तार तथा राज्य-स्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सेवाओं को सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को भी प्रमुखता दी गई है, जो चिप डिजाइन तथा निर्माण क्षमता को मजबूत कर इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई-आधारित उपकरणों के लिए अवसंरचना तैयार करेगा। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण कार्यक्रमों के लिए 8,000 करोड़ का आवंटन भी बढ़ाया गया है, जो घरेलू उर्ध्वाधर क्षमता के निर्माण में सहायक होगा।

इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का कुल बजटीय आवंटन बढ़कर 21,633 करोड़ किए जाने से एआई, डेटा प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं केंद्रित परियोजनाओं को बल मिलेगा। इंडिया एआई मिशन को विस्तारित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ का विशेष भाग निर्धारित किया गया है। डिजिटल कौशल कार्यक्रम और कंटेंट निर्माता लैब्स (15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में) की घोषणा की गई है। इससे एआई-आईटी आधारित रोजगारों और नवोन्मेषी कौशल के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। भारत की वैश्विक डिजिटल सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक हिस्सेदारी को 2047 तक 10% तक पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी।

- प्रो.ओमप्रकाश व्यास, डायरेक्टर, ट्रिपलआईटी, रायपुर

पशु चिकित्सक की व्यवस्था सार्थक निर्णय

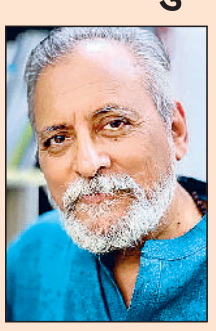

पशुधन की रक्षा के लिए पशु चिकित्सक की व्यवस्था को सुलभ बनाना बहुत सार्थक निर्णय है। महिला लघु उद्यमी के सहज बाजार लगाना बहुत ही अच्छा कदम है। मछुआरों की तरफ भी ध्यान दिया गया, ये सराहनीय है। कृषि क्षेत्र में किसानों को और नए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद थी। उद्यमियों को निर्यात के लिए थोड़ा अधिक प्रोत्साहन मिलना था। डीबीटी में कुछ परिवर्तन हो और केवल गरीबों को ही किसान सम्मान राशि प्रदान किया जाना था। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में शोध के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद थी। यह पूरी हुई। एआई और आईटी के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है। बहनों में उद्यमिता बढ़ाने और भूमि के स्वास्थ्य सुधार के लिए थोड़े अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त नवचारों पर खर्च बढ़ाने के लिए उद्योग को नई छूट की उम्मीद एक वर्ग को थी। कुछ सीमा तक यह भी पूरी हुई है।

- प्रो.एके गुप्ता, आईआईएम, अहमदाबाद (पद्म पुरस्कार प्राप्त, गुजरात ग्रासरूट्स इनोवेशन ऑग्मेंटेशन नेटवर्क के संस्थापक)

चिंतन

आम बजट में भविष्य की तस्वीर दिखाई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आम बजट 2026 एक ऐसा आर्थिक दस्तावेज़ है, जो भारत को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने की स्पष्ट मंशा दिखाता है। यह बजट विकासोन्मुखी,दीर्घकालिक सोच, रणनीतिक मजबूती और वैश्विक चुनौतियों के प्रति सजगता का परिचायक है, लेकिन साथ ही यह आम आदमी की तात्कालिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने में कमजोर भी नजर आता है। कहा जा सकता है कि यह बजट "कल" की तैयारी करता है, पर "आज" की परेशानियों को पूरी तरह संबोधित नहीं करता। वित्त मंत्री ने 85 मिनट के लंबे भाषण में अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विस्तार से बात की, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव न होना यह संकेत देता है कि सरकार फिलहाल वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता दे रही है। टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने जैसे सुधार स्वागत योग्य हैं, मगर बढ़ती महंगाई के दौर में आम करदाता को इससे सीमित ही राहत मिलेगी। बजट का सबसे मजबूत पक्ष रक्षा क्षेत्र है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पेश हुए पहले बजट में सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। रक्षा बजट को 6.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये करना और आधुनिकीकरण व हथियार खरीद पर पूंजीगत खर्च में करीब 15% की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि सरकार सेना को तकनीकी और रणनीतिक रूप से और सक्षम बनाना चाहती है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है, हालांकि सामाजिक क्षेत्रों में इसी अनुपात में खर्च न बढ़ना सवाल भी खड़े करता है। अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों से बचाने के प्रयास बजट में साफ झलकते हैं। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, ट्रंप-युग की टैरिफ मानसिकता और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में तनाव के बीच निर्यात प्रोत्साहन पर जोर दिया है। कपड़ा, चमड़ा, फिशरीज और दालों के निर्यात को बढ़ावा देने के कदम ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं। इससे रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बनेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए अस्पतालों की घोषणा, दवाओं को सस्ता करने की पहल और 17 कैंसर मेडिसिन को ड्यूटी फ्री करना आमजन के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। आयुर्वेदिक एम्स जैसी घोषणाएं भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक ढांचे से जोड़ने की कोशिश मानी जा सकती हैं। शिक्षा और युवाओं पर केंद्रित योजनाएं बजट का एक और उल्लेखनीय पहलू हैं। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की योजना डिजिटल इंडिया और क्रिएटर इकोनॉमी की दिशा में कदम है। साथ ही करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा सामाजिक समावेशन और महिला शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बजट चुनावी लोकलुभावन घोषणाओं से दूर नजर आता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों के बावजूद किसी सीधे चुनावी लाभ वाली घोषणा का अभाव बताता है कि सरकार फिलहाल दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। कुल मिलाकर आम बजट 2026 एक विज़न डॉक्यूमेंट है जो भविष्य की तस्वीर दिखाता है। यह बजट लोगों को संतुष्ट कर सकता है जो मजबूत रक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देते हैं।

विश्लेषण

डॉ.जयंतीलाल भंडारी

विकसित भारत के लिए सुधारों का बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह बजट आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत सुधारों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए तीन कर्तव्यों पर आधारित किया है। इनमें उत्पादकता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना, लोगों की आशंकाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण और सबका साथ, सबके विकास के मद्देनजर ढांचागत सुधार के साथ प्रगति करना शामिल है।

इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित किए गए हैं। यद्यपि बजट के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और आयकर भरना आसान किया गया है। बजट के नए प्रावधानों से बुनियादी ढांचा, छोटे शहर, एमएसएमई, शिक्षा, पर्यटन और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में नई पीढ़ी के लिए रोजगार के व्यापक मौके बढ़ेंगे। खास बात यह भी है कि आगामी वर्ष के बजट के तहत वित्त मंत्री राहत और विकास के बीच सूझबूझ पूर्ण संतुलन बनाते हुए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 फीसदी के स्तर पर सीमित रखने और सात फीसदी से अधिक विकास दर पाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। गौरतलब है कि नए बजट के तहत वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में धीमेपन के बीच अगली पीढ़ी के सुधार, नीतिगत स्थिरता व दीर्घकालीन विकास की रणनीति के साथ घरेलू मांग की मजबूती पर्यावरण नवाचार, उद्यमिता बुनियादी ढांचा, कृषि विकास, गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र रक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) स्वदेशी प्रोत्साहन और हरित ऊर्जा पर बड़े ऐलान किए हैं। इनके साथ-साथ भारत को वैश्विक बायो फॉर्मा केंद्र बनाने, शहरी आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण, नए राष्ट्रीय जल मार्ग, सात हाई स्पीड कोरिडोर, व्यापार सुगमता, कंटेनर निर्माण, बुजुर्गों के लिए मजबूत इकोसिस्टम, टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के विकास के लिए प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, वित्त मंत्री के समक्ष बजट तैयार करते समय चुनौतियां भी रही हैं। इन चुनौतियों में रुपये में लगातार गिरावट, अमेरिका का ऊंचा टैरिफ, मैन्युफैक्चरिंग व कृषि की धीमी रफ्तार शामिल हैं। निसंदेह वित्त मंत्री बजट के तहत गरीब, युवा, महिलाएं, किसानों के कल्याण के नए उपायों के साथ विकास योजनाओं पर भी अपने आवंटन को बढ़ाते हुए दिखाई दी हैं। बजट में रोजगार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा वेयरहाउसिंग संबंधी प्रोत्साहन, रियल एस्टेट सेक्टर और आवास सेक्टर को प्रोत्साहन, डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने तथा स्वच्छ ऊर्जा के लिए अधिक आवंटन करते हुए दिखाई दी हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि इस बजट में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रेलवे, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और

क्षमता संवर्धन के साथ दीर्घावधि वृद्धि, वैश्विक क्षमता निर्माण और एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड के सुधार उभरकर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बजट के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने संबंधी रणनीतियां भी दिखाई दी हैं। युवाओं के रोजगार बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने, प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। सीतारमण बजट में खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए भी आपूर्ति संबंधी नए कदमों के साथ आगे बढ़ी हैं। बजट में वित्त मंत्री ने रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखकर नए रोजगार अवसरों को निर्मित करने की रणनीति भी अपनाई है। विकसित भारत के लक्ष्य के मद्देनजर डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान भी बजट में दिखाई दे रहे हैं। नए बजट में हर क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को अहमियत हेतु प्रावधान किए गए हैं, ताकि भारत एआई का वैश्विक हब बन सके। सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए भी बजट में अधिक धन का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में भारत को दुनिया के बाजार में और अधिक प्रभावी रूप से जुड़ने और भारत को निर्यात का नया हब बनाने के लिए नई रणनीति प्रस्तुत की है।

भारत को यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बाद दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के प्रोत्साहनमूलक प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ से प्रभावित निर्यात क्षेत्रों को भी राहत देने के मद्देनजर वित्त मंत्री नए निर्यात प्रोत्साहनों की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं।निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने इस बजट में सीमा शुल्क के लिए जहाँ राहत दी है, वहीं सीमा शुल्क में सुधार भी किए है। यह बजट इसलिए भी खास रहा है, क्योंकि यह बजट पुराने टैक्स युग से नए टैक्स युग की दहलीज पर खड़ा बजट है। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से करीब 60 साल पुराने टैक्स कानून की जगह नया इनकम टैक्स कानून लागू किया है। इससे देश के करोड़ों आयकरदाता लाभांवित होंगे। साथ ही नई श्रम संहिताएं भी आगामी वित्तीय वर्ष में लागू होने से श्रम उत्पादकता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास का नया अध्याय दिखाई देगा। निश्चित रूप से वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तुत बजट कोई साधारण वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट देश के आर्थिक परिदृश्य को ऐतिहासिक मोड़ देने वाला बजट है। इस बजट से जहां देश में साहसिक सुधारों का नया युग शुरू हो सकेगा, वहीं आम आदमी के लिए अधिक राहत और देश के लिए तेज विकास का नया परिदृश्य निर्मित होगा।

उम्मीद करें कि एक ओर वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 के बजट के बजट के लक्ष्य के तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 फीसदी तक रखने में कामयाब होगी। उम्मीद करें कि इस अभूतपूर्व बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

> वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। यद्यपि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया है और आयकर भरना आसान किया गया है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

आम बजट

प्रमोद भार्गव

आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट

नए आम बजट से उम्मीद की जा रही थी कि यह आयकर की सारिणी में छूट और पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकलुभावन बजट होगा, लेकिन यह बजट इसके विपरीत आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट है। इसके स्थाई और रोजगार देने वाले परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। इस बजट की उम्मीदों में तमाम आर्थिक उथल-पुथल और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की बुनियाद रख दी है। इस समय भारत उद्योग,प्रौद्योगिकी और दवाओं के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है, किंतु यह बजट कालांतर में चीन को चुनौती बनने वाला है। इस बजट में दुर्लभ खनिजों के उत्खनन को बढ़ावा देने के द्वार खोले जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खनिज के साथ कृषि भी है। अतएव ईयू से जो संधि हुई है, उसके तहत भारत को स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, पेपर, ग्लास, तेल रिफाइनरी और खाद के निर्यात का लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से भारत भूमि को कुदरत ने अटूट प्राकृतिक संपदा दी हुई है। इस संपदा का उत्खनन और उसका उपयोग देश के लोगों के लिए हो, इस नजरिए से दुर्लभ खनिजों के उत्खनन के लिए बजट में ओडिशा, केरल और आंध्रप्रदेश के बीच गलियारा बनाए जाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए जाएंगे। साथ ही वस्त्र, खेलकूद सामग्री,जैविक दवाओं,कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। रसायन पार्क विकसित होंगे। सेमीकंडक्टर मिशन दो की शुरुआत की जाएगी। चूंकि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के उपाय निरंतर कर रही है, इस हेतु सेमीकंडक्टर की उपलब्धता जरूरी है। इस दृष्टि से यह उत्पादन और निर्माण के ढांचागत विकास को स्थापित करने का महाबजट है। दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा हेतु संसद के मॉनसून सत्र में माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इस नए कानून से व्यवसायियों को लीज पर खनन करने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लीथियम, कोबाल्ट, निकल, हीरा जैसे दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा भी मिल गई है। भारत इन खनिजों के लिए अब तक चीन पर निर्भर था, लेकिन चीन ने इनके निर्यात पर रोक लगा दी थी। यही वे खनिज हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और अंतरिक्ष उपकरणों में काम आते हैं। हालांकि ट्रंप द्वारा लगाए गए अनर्गल टैरिफ के बाद चीन ने भारत को उपरोक्त खनिज देने का वादा किया हुआ है। ईयू से समझौते के बाद दुर्लभ खनिजों के आयात-निर्यात का दायरा विस्तृत हो गया है। इसीलिए भारत अब अपनी शर्तों पर विकसित देशों के साथ व्यापार भी करेगा। अब माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पारित हो जाने से उद्योगपति निवेश के लिए आगे आएंगे। मध्यप्रदेश की धरती हीरा और सोना तो उगलती ही है, तांबे और चूने का यहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कटनी में चूने के भंडार हैं। शडहोल और उमरिया में कोयला एवं बॉक्साइड, छिंदवाड़ा में कोयला, बैतूल में ग्रेफाइड और सतना में सिमेंट के भंडार भरे पड़े हैं। मध्यप्रदेश में ईंधन खनन के लिए 12 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। कोयला आधारित 37 प्रतिशत मीथेन का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। जबलपुर में सोने के नए भंडार मिले हैं। ग्रेफाइट सहित 30 दुर्लभ खनिज तत्वों की खोज की गई है। इनके उत्खनन व प्रसंस्करण के बाद लीथियम और लौह अयस्क के लिए सीधी में एक क्षेत्र चिन्हित कर दिया गया है। इसके अलावा बजट में जैविक औषधीय दवाओं के उत्पादन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। बायोफार्मा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। सरकार आयुर्वेद दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देगी। इन दवाओं का निर्माण इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये रोग को जड़ से दूर करती हैं। सात द्रुत गति के रेल गलियारे बनेंगे। पटना और वाराणसी में जहाजों की मरम्मत के कारखाने खुलेंगे। छोटे नगरों में तीर्थस्थल विकसित होंगे। इस उपाय से छोटे नगरों में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। इससे स्थानीय लोगों को धर्म संबंधी रोजगार मिलेंगे। एक जिला,एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया गया है। साफ है यह बजट अन्य आम बजटों से एकदम अलग है। इसमें मतदाता को लुभाने और आयकरदाताओं को संतुष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उद्योग केंद्रित बजट है, जिसके स्थाई और फलदायी परिणाम धीमी गति से आएंगे। जो देश की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती देंगे, बल्कि देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

योग के सभी सूत्र सुदृढ़ जीवन की आधारशिला

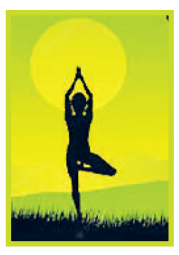

संकलित

दर्शन

योग प्राचीन काल से भारतीय आध्यात्मिक संचेतना का केंद्र रहा है। इसके आदिम सूत्रधार परमयोगी भगवान शिव हैं। योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता रहा है। समाधि अर्थ में इसका प्रयोग आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए किया जाता है, जब साधक अपनी साधना की चरमावस्था में परमात्मा से एकाकार होकर उसका साक्षात्कार कर लेता है। अग्निपुराण में भी मन एवं आत्मा तथा आत्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा गया। सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष का भेद होने पर भी पुरुष का आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना योग कहलाता है। कठोपनिषद् के अनुसार, जब इंद्रियां मन के साथ और मन अविचल बुद्धि के साथ स्थिर हो जाता है तो यह अवस्था योग की होती है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने 'योगः कर्मसु कौशलम्' कहकर योग का जो स्वरूप अजरुन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह सामान्य जन के सर्वाधिक निकट है। कोई भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए योग को सिद्ध कर सकता है। योगसूत्र के प्रणोता महर्षि पतंजलि संयमन अर्थ में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उनके अनुसार यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा आदि आठ अंगों से संपन्न प्राणायाम की विविध क्रियाएं योग कहलाती हैं। इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। बुद्धि में स्थिरता आती है। चिंतन उत्कृष्ट होता है। मन में सद्विचारों का उदय होता है। नकारात्मक प्रवृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। परिणामतः आत्मिक और शारीरिक शक्तियों में वृद्धि होती है।

मन का भोजन हमारे विचार

संकलित

प्रेरणा

एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सत्संग में काफी लोग बैठे हुए थे। भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और उसने बुद्ध से पूछा कि तथागत मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। कृपया बताइए, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध के साथ ही सत्संग में बैठे हुए लोगों ने भी ये प्रश्न सुना, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया फिर से अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा कि एक बार और अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने एक बार और अपनी बात कह दी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन हैं। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे, तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच-विचार करना बंद कर देना चाहिए। तब ही हम ध्यान कर पाएंगे। जब मन विचारों से खाली हो जाएगा, तब ही हम ध्यान कर पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से ध्यान के बारे में प्रश्न तीन बार पूछा था और बुद्ध ने भी तीन बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बुद्ध ने तीन बार उत्तर दिया तो लोगों ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति से तीन बार प्रश्न पूछा और उत्तर भी तीन बार ही दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मैं इन सज्जन से तीन बार प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं प्रश्न के लिए इनकी गंभीरता को परखना चाहता था। जब मुझे लगा कि ये अपने प्रश्न के लिए गंभीर हैं, तब मैंने उत्तर भी तीन बार दिया, ताकि मेरी बात इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए।

थाईपुसम त्योहार

भगवान मुरुगन की जयंती के अवसर पर एक अपनी जीभ में सांग छेद कर थाईपुसम त्योहार में हिस्सा ले रहा है।

आज की पाती

उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करना जरूरी

विज्ञान ने हमें हर मौसम से बचने के लिए बहुत सी चीजें दी हैं। लेकिन अगर हम इनका सावधानी से प्रयोग न करें तो यह हमारे लिए कभी भी हानिकारक बन सकती हैं और अक्सर खबरें भी पढने और सुनने को मिलती हैं कि इन चीजों के प्रयोग करते कई बार हादसा हो गया। सर्दियों में गैस गीजर, कोयले की अंगीठी और अन्य गर्मी प्रदान करने वाले उपकरण लोगों की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। सर्दियों के मौसम में नहाने के लिए लोग गैस से चलने वाले गीजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके प्रयोग में जरा सी भी असावधानी किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। गैस गीजर को बाथरूम में लगाने के साथ-साथ एक खिडक़ी जरूर रखें। लोगों को चाहिए कि जहां गैस गीजर लगा हो वहां हवा बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। - *संजय शर्मा, दुर्ग*

2 फरवरी पर विशेष

वेटलैंड

वेटलैंड जो अंग्रेजी का शब्द है के लिए हिंदी में अनेकानेक शब्दों का उपयोग देखने में आता है आर्द्र ,जलोध,नम,दलदली भूमि ये सभी शब्द एक ही मायने और अर्थ प्रकट करते हैं और इनकी उपस्थिति हमारे जैव मंडल के लिए अति आवश्यक है जिसमें जल चर थल घर,नभ चर समाहित हैं इन सभी की जीवन सुरक्षा में वेट लैंड की भूमिका महत्वपूर्ण है जिसका संरक्षण संवर्धन आवश्यक है इन उदाहरणों से समझा जा सकता है झील, ताल तलैया, पोखर, तालाब या वो सभी जल संग्रहण के केंद्र जहां पानी की गहराई 6 मीटर से ज्यादा न हो ये सभी स्थान वेटलैंड (नम भूमि) को इंगित करते हैं जो मिट्टी, पानी,जैव विविधता को पुष्ट कर जीव जगत को सुरक्षित जीवन प्रदान करते रहते हैं।

वेटलैंड प्राकृतिक रुप से जल शोधन का कार्य कर जल को साफ सुथरा कर पेयजल आपूर्ति कर अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं वहीं ये बाढ़ आने पर इसकी रोकथाम कर प्राकृतिक बफर बन ढाल का कार्य कर सभी की सुरक्षा करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में वेट लैंड अग्रणी भूमिका में हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु रक्षक का कार्य प्राकृतिक रुप से करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है आज जिस प्रकार से भी जलवायु परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसे संतुलित रखने में आद्र भूमि अपनी महती भूमिका निभाते दिखते हैं।

इनकी आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988 के अंतर्गत भारत शासन द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 लागू कर इसकी सुरक्षा को सर्वोपरि माना वहीं राज्य शासन द्वारा 17.12.2018 को राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन कर इसकी सुरक्षा हेतु कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का परिपालन सुनिश्चित किया एवं सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठन सुनिश्चित किया गया इस प्रकार के निर्णयों से ये बात तो स्पष्ट होती है कि शासकीय और गैर शासकीय सभी स्तरों पर वेटलैंड को संरक्षित संवर्धित करने की भावना बलवती होती जा रही है जो एक शुभ संकेत है इस प्रकार के नजरिए से हमारे नगरीय और ग्रामीण वेटलैंड को असमय हो रही मृत्यु से बचाया जा सकेगा साथ ही भू-जल स्तर जो तेजी से नीचे जा रहा है उसे भी बचाया जा सकेगा और अस्तित्व-सह अस्तित्व के भाव से समाज परिवार और प्रकृति के भाव सुरक्षित रह सकेंगे।

-प्रभात मिश्र

करंट अफेयर

इजराइल की रफाह सीमा क्रॉसिंग खोलने की घोषणा

इजराइल ने फलस्तीनियों के सीमित आवागमन के मद्देनजर गाजा की मिस्र के साथ रफाह सीमा क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रफाह सीमा क्रॉसिंग पर रविवार को चहल-पहल देखी गयी। रफाह सीमा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना इजराइल-हमास संघर्षविराम के आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल ने रविवार को घोषणा की कि रफाह क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोल दिया गया है। गाजा को मानवीय सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली इज़राइली सैन्य एजेंसी सीओजीएटी ने एक बयान में कहा कि क्रॉसिंग को पूर्ण संचालन के लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है और तैयारियां पूरी होने के बाद गाजा के निवासी यहां से आवागमन शुरू कर सकेंगे। मिस्र के एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि फलस्तीनी सुरक्षा अधिकारी मिस्र वाले द्वार से होकर क्रॉसिंग में दाखिल हुए और फलस्तीनी द्वार की ओर बढ़े, जहां वे एक यूरोपीय संघ मिशन के साथ जुड़ेंगे, जो प्रवेश और निकास की निगरानी करेगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि एंबुलेंस भी मिस्र वाले द्वार से होकर गुजरीं।

ऑफ बीट

रात में पसीना आने के कई कारण हो सकते हैं

पसीना आना शरीर की शीतलन प्रणाली का एक सामान्य हिस्सा है, जो गर्मी छोड़ने और शरीर के इष्टतम तापमान को बनाए रखने में मदद करता है।

लेकिन नियमित रूप से रात में जागना, अत्यधिक पसीने से भीगना सही नहीं है। मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस, अंत :स्रावी तंत्र का हिस्सा है और शरीर के लिए तापमान नियंत्रण केंद्र है। इसमें तापमान सेंसर होते हैं जो केंद्रीय रूप से (अंगों में) और परिधीय रूप से त्वचा में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं (थर्मोरिसेप्टर्स) से जानकारी प्राप्त करते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स शरीर के तापमान में बदलाव का पता लगाते हैं, हाइपोथैलेमस को वापस संकेत भेजते हैं। ये संकेत या तो शरीर को ठंडा करने के लिए पसीने को सक्रिय करेंगे या शरीर को गर्म करने के लिए कंपकंपी को सक्रिय करेंगे। उम्र या लिंग कोई भी हो, किसी को भी रात में पसीना आने का अनुभव हो सकता है। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को रात में पसीना अधिक आता है, इसका मुख्य कारण रजोनिवृत्ति और संबंधित बदलते हार्मोन स्तर हैं। ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रोजन के स्तर में बदलाव से नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो हाइपोथैलेमस में तापमान विनियमन को प्रभावित करते हैं।

रविवार को शेयर बाजार खुला और गिरा धड़ाम से, बजट में एसटीटी पर सख्ती से टूटा

- सेंसेक्स से 8 लाख करोड़ रुपए साफ, निवेशकों में बेचैनी

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

आम बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) से जुड़े प्रावधानों ने शेयर बाज़ार की धारणा को गहरी चोट पहुंचाई है। बजट के तुरंत बाद आई भारी बिकवाली के चलते शेयर बाज़ार से करीब 8 लाख करोड़ रुपये का बाज़ार पूंजीकरण घट गया। विश्लेषकों का मानना है कि एसटीटी से जुड़ी सख्ती और स्पष्ट राहत के अभाव ने निवेशकों, खासकर शॉर्ट-टर्म और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को निराश किया।

एसटीटी बना गिरावट की बड़ी वजह

बजट में सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से एसटीटी के दायरे और प्रभाव को लेकर जो संकेत दिए, उससे बाज़ार में लागत बढ़ने की आशंका गहराई। विशेषज्ञों के मुताबिक, एसटीटी में किसी भी तरह की वृद्धि या उसमें राहत न देना सीधे तौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम, खासकर डेरिवेटिव्स और इंट्रा-डे कारोबार को प्रभावित करता है। यही वजह रही कि बजट के बाद पहले ही सत्र में आक्रामक बिकवाली देखने को मिली।

छोटे निवेशक और ट्रेडर सबसे ज्यादा प्रभावित

एसटीटी का बोझ सीधे हर सौदे पर पड़ता है, चाहे निवेशक को मुनाफा हो या नुकसान। इस कारण छोटे निवेशक, डे-ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा दबाव में आए। बाज़ार जानकारों का कहना है कि इससे इक्विटी बाज़ार की आकर्षण क्षमता घटती है और पूंजी का रुख दूसरे एसेट क्लास की ओर मुड़ सकता है।

ब्रोकरेज और एक्सचेंज शेयरों पर दबाव

एसटीटी से जुड़ी चिंताओं का असर ब्रोकरेज, एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों पर भी साफ दिखा। कारोबार घटने की आशंका से इन कंपनियों के शेयरों में औसत से कहीं ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

सरकार का पक्ष और दीर्घकालिक तर्क

सरकार का कहना है कि बजट में राजकोषीय संतुलन बनाए रखना जरूरी है और एसटीटी जैसे कर बाज़ार से स्थिर राजस्व का स्रोत हैं। साथ ही सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर खर्च बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे दीर्घकाल में आर्थिक गतिविधियों और कॉरपोरेट मुनाफे को सहारा मिल सकता है।

आगे क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार एसटीटी पर स्पष्टीकरण या भविष्य में पुनर्विचार का संकेत देती है, तो बाज़ार की धारणा में सुधार आ सकता है। फिलहाल निवेशकों को सतर्क रहने और गुणवत्ता वाले शेयरों पर दीर्घकालिक नजर रखने की सलाह दी जा रही है। बहरहाल, बजट में एसटीटी को लेकर उठे सवालों ने यह साफ कर दिया है कि शेयर बाज़ार केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि लेन-देन की लागत से भी गहराई से प्रभावित होता है। जब तक इस मोर्चे पर भरोसा बहाल नहीं होता, बाज़ार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। सोमवार को बाजार के हालत पर इसकी संभावनाओं पर रविवार देर शाम तक विशेषज्ञों ने चुप्पी बनाए रखना ही ठीक समझा।

आम बजट में 7 रणनीतिक और अग्रिम क्षेत्रों में विनिर्माण पर दिया गया जोर

भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करेंगे

इलेक्ट्रॉनिकी कल-पुर्जा निर्माण योजना का परिव्यय बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया

- *उपकरण और सामग्री उत्पादन, भारतीय आईपी का पूरी तरह डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा*
- *खनिज समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की मदद के लिए समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना की*
- *5 वर्षों की अवधि में 10 हजार करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण परिवेश के निर्माण की योजना*

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय बजट 2026-27 में सात रणनीतिक और अग्रिम क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करने पर जोर दिया गया है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम बजट में 'पहला कर्तव्य' के तहत छह क्षेत्रों का हिस्सा होगा।

भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय बजट में अगले पांच वर्षों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'बायोफार्मा शक्ति' का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए उचित प्रणाली का निर्माण होगा। इसके लिए बजट में अभिकल्पित कार्यनीति में तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के साथ बायोफार्मा केन्द्रित नेटवर्क और सात मौजूदा संस्थानों का अपग्रेडेशन शामिल है। इसमें एक हजार से अधिक प्रत्यायित भारत क्लीनिकल ट्रायल्स केन्द्रों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। केन्द्रीय बजट में वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत करने और एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा कैडर तथा विशेषज्ञों के जरिए समय से अनुमोदन के लिए प्रस्ताव किया गया है।

देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमता में विस्तार करने और भारत सेमीकंडक्टर मिशन (1.0) को आधार मानकर केन्द्रीय बजट में उपकरण एवं सामग्री निर्माण, भारतीय आईपी का पूरी तरह से डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन (2.0) शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए सरकार का ध्यान उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्रों पर रहेगा।

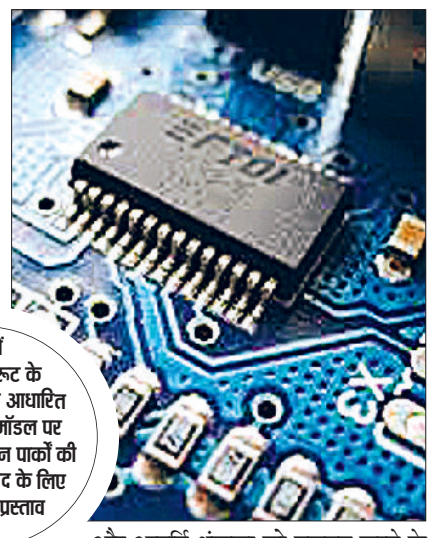

राज्यों को चैलेंज रूट के जरिए कलस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल पर असमर्पित रसायन पार्कों की स्थापना में मदद के लिए योजना का प्रस्ताव

अप्रैल 2025 में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय 22 हजार 919 करोड़ रुपये था। बजट 2026-27 में इस राशि को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय बजट में खनिज समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना में मदद करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने चैलेंज रूट के जरिए कलस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल पर तीन रसायन पार्कों की स्थापना में राज्यों को मदद करने के लिए एक योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मजबूत पूंजीगत वस्तु सामर्थ्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता का निर्धारक है। केन्द्रीय बजट में दो स्थानों पर उच्च प्रौद्योगिकी टूल रूम स्थापित किए जाएंगे। इसकी स्थापना सीपीएसई डिजिटल रूप से समर्थित ऑटोमेटिड सर्विस ब्यूरो के रूप में करेगी। जो स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने और कम लागत पर उच्च परिशुद्धता वाले घटकों के डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। निर्माण और अवसंरचना उपकरण (सीआईई) को बढ़ावा देने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च घरेलू विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के स्तर पर उन्नत सीआईई को मजबूत करना है। यह बहुमंजली इमारत में लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, बड़ी और छोटी से लेकर मेट्रो और ऊंचाई वाले स्थानों पर सड़कों के लिए सुरंग संबंधी उपकरण हो सकते हैं। बजट में वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण परिवेश के निर्माण के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए, पांच वर्ष की अवधि में 10 हजार करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन है।

श्रम गहनन वस्त्र उद्योग के लिए, बजट में पांच उपभागों वाले एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। पहला, रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और आधुनिक फाइबरों में आत्म-निर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना; दूसरा, मशीनरी प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक कलस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना; तीसरा, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं मजबूत करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम; चौथा, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र तथा परिधानों को बढावा देने के लिए टैक्स इको पहल; पांचवां, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 ।

तकनीकी वस्त्रों के मूल्यवर्धन पर ध्यान देते हुए बजट में चुनौती मूड में वृहद वस्त्र उत्पाद स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, खादी हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ बनाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे वैश्विक बाजार में जगह बनाने और ब्राडिंग में मदद मिलेगी। बजट में कहा गया है कि इससे प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाया जाएगा और सहायता भी मिलेगी। इस पहल से हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा।

बजट पेश करने के दौरान श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले खेलकूद के किफायती सामानों के लिए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में उभरने की संभावना है। बजट में उपकरण डिजाइन के साथ-साथ सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद के सामानों के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव किया गया है।

रायपुर सांसद बृजमोहन ने कहा

छत्तीसगढ़ को 52 हजार करोड़ की हिस्सेदारी, यह खोलेगा विकास का नया द्वार

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आम बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि यह विकसित भारत के लिए एक सफ़ल नींव साबित होगा।साथ ही इससे खुशहाल छत्तीसगढ़ के लिए भी रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए इस साल 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित है। जो रोज़गार के नए द्वार खोलेंगे समूचे बजट में पिछली बार के 49 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 53 लाख करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। खर्च प्रस्ताव में 10 फ़ीसदी की ऐसी बढ़ोतरी युवाओं को अधिक से अधिक रोज़गार उपलब्ध करायेगी छत्तीसगढ़ को भी इस साल 42 हजार करोड़ की बजाए 52 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जिससे राज्य में विकास के नये रास्ते निकलेंगे। युवाओं और महिला बाल विकास पर भी और बेहतर ढंग से कार्य हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल के लिए माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि इससे खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इस पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कदम राज्य की अपार खनिज संपदा से खुशहाली के अनेक रास्ते निकालेंगे। राज्य की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रेल्वे कॉरिडोर से भी छत्तीसगढ़ में विकास बढ़ेगा। यह बजट देश को 2047 तक विकसित करने के लिए बनाया गया है। 10 हजार करोड़ का एमएसएमई फंड देश को विकास की राह में और आगे ले जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए यह घोषणा की कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यगों (एमएसएमई) की सहायता के लिए मझोले (श्रेणी-दो) और छोटे (श्रेणी-तीन) शहरों में 'कॉरपोरेट मित्रों' का एक दस्ता तैयार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताया कि केंद्र सरकार ने छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेज को इंसेंटिव देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड शुरू करने की योजना की घोषणा की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस साल का बजट रक्षा, बुनियादी ढांचे, पूंजीगत व्यय, बिजली और किफायती आवास पर केंद्रित है। इससे सामाजिक कल्याण, प्राथमिकताओं और वित्तीय विवेक के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा गया है।

स्टार्टअप, डीप टेक और डेटा सेंटर का नया गढ़ बनेगा हरियाणा : नायब

कहा, हरियाणा बनेगा एआई नवाचार का केंद्र, विश्व बैंक देगा 470 करोड़ रुपए की मदद

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा स्टार्टअप, डीप टेक और डेटा सेंटर का नया गढ़ बनेगा। उन्होंने शनिवार देर सायं चंडीगढ़ में आयोजित टी.आई.ई.एआई शिखर सम्मेलन–2026 को संबोधित करते हुए यह बात कही। वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया के संकल्प को साकार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि "ग्लोकल एआई – रियल इम्पैक्ट" केवल एक विषय नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता है, जिसमें वैश्विक सोच को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि दि इंडस एंटरप्रेन्योर्स चंडीगढ़ द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन भविष्य की तकनीक, नवाचार और उद्यमिता को नई दिशा देने वाला सशक्त मंच है। इस अवसर पर पूर्व राज्यमंत्री असीम गोयल, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जे. गणेशन तथा टी.आई.ई. चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट पुनीत वर्मा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल तकनीक नहीं रह गई है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एआई के अनुसंधान, नवाचार और उत्तरदायी नीति निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि एआई स्वास्थ्य सेवाओं में रोगों की पहचान और उपचार को अधिक सटीक बना रही है, शिक्षा में व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया को सशक्त कर रही है तथा कृषि क्षेत्र में किसानों को उत्पादन बढ़ाने, बेहतर बाजार और मूल्य संवर्धन में सहायता प्रदान कर रही है। छोटे और मध्यम उद्यम एआई के माध्यम से अपनी दक्षता बढ़ाकर वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एआई को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा एआई मिशन' स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग 470 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है। इस मिशन के अंतर्गत गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक एआई हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

कहा- बंगाल में भाजपा की आगामी विधानसभा चुनाव में पराजय निश्चित

ममता आज करेंगी सीईसी से मुलाकात एसआईआर से जुड़े मुद्दे रखेंगी सामने

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में हार सुनिश्चित होने के कारण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री बनर्जी रविवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार की शाम दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने वाली हैं। ममता बनर्जी सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सीईसी से मुलाकात के दौरान मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़े मुद्दे उठाएंगी। उन्होंने कहा, मैं उन्हें बताऊंगी कि एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है।

उन्होंने दावा किया कि राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा की आगामी विधानसभा चुनाव में पराजय निश्चित है। बनर्जी ने कहा कि जिस कारण भाजपा एसआईआर का दुरुपयोग कर रही है, वह सबके सामने है। भाजपा को चुनौती देते हुए ममता ने कहा, मैं उनसे कहूंगी, अगर हिम्मत है तो राजनीतिक लड़ाई लड़ो। हम इंच-इंच लड़ने के लिए तैयार हैं।

वे (भाजपा) संघीय ढांचे को कैसे खत्म करना चाहते हैं? मैं सब बताऊंगी। हमने क्या किया, यह भी बताऊंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने सांसदों को एसआईआर के नाम पर की जा रही कोशिशों के बारे में जानकारी देंगी। उन्होंने कहा, भाजपा नेता जानते हैं कि बंगाल में हारेंगे। इसलिए एसआईआर का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर भाजपा में हिम्मत है, तो मैं उनसे अपील करूंगी कि चुनाव आयोग (ईसीई) और एजेंसियों का इस्तेमाल करने के बजाय राजनीतिक और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव लड़ें।

एनसीबी के विलय पर असमंजस की

शरद पवार मुंबई पहुंचे तो बारामती लौट गईं डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार

एजेंसी ⏭ मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर असमंजस की स्थिति है। इसी बीच, एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार रविवार सुबह बारामती से मुंबई के लिए रवाना हो गए, जबकि नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार देर रात बारामती लौट आईं। शरद पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के चार दिन बाद मुंबई के लिए रवाना हुए। सुनेत्रा ने शनिवार को मुंबई में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुणे जिले के बारामती स्थित अपने आवास लौट आईं। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही अटकलों के बीच यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि शरद और सुनेत्रा के बीच कोई मुलाकात या बातचीत हुई या नहीं।

एयर इंडिया ने भरी शंघाई से नई दिल्ली के बीच पहली उड़ान

छह साल के बाद नई दिल्ली और शंघाई के बीच हुई सीधी उड़ान सेवाओं की शुरुआत, इससे संबंध सुधरेंगे

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

भारत और चीन के बीच पिछले साल पूरी तरह से खत्म हुए एलएसी विवाद के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए जारी कवायद के बीच एक खुशखबरी सामने आई है। जिसमें ये पता चला है कि भारत ने करीब छह साल के लंबे अंतराल के बाद रविवार को एक बार फिर से नई दिल्ली से शंघाई के बीच सीधी उड़ान सेवाओं की शुरुआत कर दी है। पूर्व में 2020 से इस पर रोक लगी हुई थी। दोनों देशों के बीच हवाई यातायात के नजरिए से यह एक बेहद महत्वपूर्ण लिंक है। जिस पर उड़ान सेवाओं का आगाज एयर इंडिया ने किया है। 1 फरवरी को ही एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान ने शंघाई के पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए पहली उद्घाटन उड़ान भरी है। जिसमें कुल करीब 230 यात्रा सवार थे। एयर इंडिया इस रूट पर सप्ताह में चार बार अपनी उड़ान सेवाओं का संचालन करेगी। विमानन कंपनी का यह निर्णय इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि दोनों देशों के बीच आमजन में आवाजाही को लेकर रुचि बरकरार है। संभव है कि इसकी मदद से भारत और चीन के बीच आगामी वक्त में शिक्षा, पर्यटन और व्यापार के संबंध में भी लोगों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिले।

महावाणिज्य दूतावास की प्रतिक्रिया

शंघाई में भारत के महादूवाणिज्य-दूत प्रतीक मिश्रा ने शंघाई के पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एयर इंडिया की फिर से शुरू हुई इस नॉनस्टॉप उड़ान सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एक्स पर पोस्ट में महावाणिज्य दूतावास ने कहा, यह उद्घाटन समारोह 6 साल बाद दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान अपने संबोधन में प्रतीक मिश्रा ने खासतौर पर इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे बेहतर हवाई संपर्क दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क, व्यापार, पर्यटन, वाणिज्य, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।

बजट से पहले आमजन को झटका

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हो गया 49 रु. का इजाफा

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय बजट से ठीक पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 49 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 फरवरी से लागू हो गई है। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरों के मुताबिक, दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमत अब बढ़कर 1,740.50 रुपए हो गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे लोगों के रसोई का बजट बिगड़ सकता है।

बजट-2026 पर मीम्स के माध्यम से कुछ व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाएं

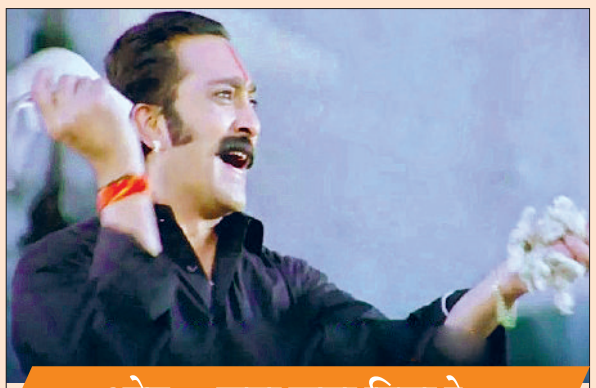

ओए... चूना लगा दिया रे...

ये... ले और चाहिए तो बता देना बहुत माल है... अपने पास....

अब तो पैसा ही पैसा है भैया

सिगरेट पर 40% जीएसटी

का कहें भैया... बहुत मारे हैं

मैं तो टैक्स लूंगी, मेरा थैला तो भर गया, अब तुम जानो भैया

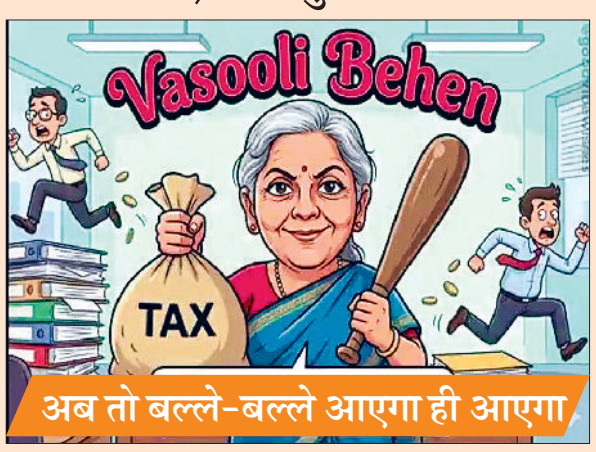

अब तो बल्ले-बल्ले आएगा ही आएगा

बजट के बाद बीड़ीबाजों की हालत में भी परिवर्तन दिखाई दिया

बजट से पहले

बजट के बाद

क्या मीम्स बनाने वालों को बजट समझ आया?

वैसे तो हर बजट पर मीम्स बनते हैं। पर, इस बार मीम्स की बाढ़ नहीं आई क्योंकि, बजट तत्काल प्रभाव देने वाला नहीं है। वह दूरगामी प्रभाव का बजट है। इसलिए, मीम्स कम्युनिटी को बजट जल्दी और ठीक से समझ नहीं आया। यानि, हमारी वित्त मंत्री मीम्स वालों की तीखी प्रतिक्रियाओं से फिलहाल बच गईं। पर, जितना भी बजट समझ आया, इन मीम्स वालों ने उसका अपने अंदाज में आनंद लिया। आप भी लीजिएगा।

सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री सीतारमण का प्रतीकात्मक मीम्स दिनभर वायरल होता रहा। लोगों ने देखा और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दीं कहा- दीदी कह रहीं हैं लो अब आप जानो

आज पूरे दिन निर्मला ताई ही चर्चा में रहीं हैं क्यों?

बल्ले-बल्ले

यही तो...

ज्यादा भौंक रहे हो, बताऊं क्या....

ये मीम्स भी खूब वायरल हुआ। कुत्तों का झुंड भौंकने लगा तो फायरिंग कर चुप करा दिया

बजट से किस पर क्या असर होगा

चांदी में निवेश करने वाले

सोने में निवेश करने वाले

निवेशकों पर बजट का असर

दैनिक कारोबारियों का हाल भी कुछ इस तरह बयां किया गया

लंबे समय तक निवेश करने वालों की हालत इस तरह दिखी

उद्योगपति मुकेश अंबानी बजट पर शर्माए, निर्मला बोलीं-ठीक

कवियों की नजर में बजट

विकसित भारत के लक्ष्य की बात

नीतेश व्यास
भोपाल

विकसित भारत के लक्ष्य की बात।
2026 के बजट में सरकार की सौगात।
आत्मनिर्भर भारत की संकल्पित चाह।
राष्ट्रीय फाइबर योजना से बनेगी राह।
कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारियों से जल्द मिले आराम।
नए बजट में सरकार ने सस्ते किए दवाओं के दाम।
इलेक्ट्रिकल व्हीकल सोलर पैनल ग्रीन एनर्जी को मिला दम।
ऐसे उपकरणों के उत्पादन बढ़े इसलिए हुई ड्यूटी कम।
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज शुरू करने का प्रस्ताव।
खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प कला की मजबूती में दिखेगा प्रभाव।
न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में भी दिखेगी ब्यूटी।
आयातित उपकरणों पर नहीं लगी कस्टम ड्यूटी।

बजट न डराता है, न हंसाता है

डॉ.संदीप शर्मा
धार

बजट ऐसा आया है कि न टैक्स पूरी तरह डराता है
न पूरी तरह हंसाता है
मध्यम वर्ग की आदत के अनुसार संयम में
खुश रहना सिखाता है
फिर जेब हल्की होने की तैयारी है
पर हां - इरादे बहुत भारी हैं
पीड़ा पर कर का भार नहीं है
कम यह भी उपहार नहीं है
सस्ते रेशम, जूट की बात
राहें कठिन, पर सस्ते बूट की सौगात
यह नहीं कह सकते कि विकास का मौका नहीं है
सपने बढ़े हैं इरादों में धोखा नहीं है

बजट: खेल सामग्री क्षेत्र के लिए 500 करोड़, खेलो इंडिया को फिर से सर्वाधिक आवंटन

एजेंसी ▶▶| नयी दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय के आवंटन में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की गई, जिसमें खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है क्योंकि उसको पहली बार 500 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 4479.88 करोड़ रुपये है जो 2025-26 के संशोधित आवंटन 3346.54 करोड़ रुपये से 1133.34 करोड़ रुपये अधिक है। राष्ट्रीय शिविरों के आयोजन और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के लिए आवंटित राशि को 880 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 917.38 करोड़ रुपये कर दिया गया है। देशभर के स्टेडियमों के रखरखाव और उनके उपयोग की जिम्मेदारी भी साइ की होती है। हालांकि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी एजेंसी का बजट क्रमशः 28.55 करोड़ रुपये से घटाकर 23 करोड़ रुपये और 24.30 करोड़ रुपये से घटाकर 20.30 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उच्च गुणवत्ता वाले और किफायती खेल सामग्री के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की भारत की क्षमता पर जोर दिया और इस तरह से खेल मंत्री मनसुख मांडविया के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने कहा, ''मैं खेल सामग्री के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव करती हूं जिससे उपकरण डिजाइन के साथ-साथ खेल सामग्री के क्षेत्र में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।''

खेल इकाइयों और योजनाओं के लिए आवंटित राशि की सूची

▶▶| खेलो इंडिया मिशन	924.35 करोड़
▶▶| भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)	917.38 करोड़
▶▶| खेल सामग्री निर्माण	500.00 करोड़
▶▶| राष्ट्रीय खेल संघ	425.00 करोड़
▶▶| मेरा युवा भारत	655.22 करोड़
▶▶| कॉमनवेल्थ गेम्स 2026	50.00 करोड़
▶▶| खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	40.00 करोड़

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सहायता राशि 50 करोड़ हुई

अभी तक के बजट में खेल सामग्री क्षेत्र से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। खेल मंत्रालय ने इस आवंटन का स्वागत किया और कहा कि खेल सामग्री उद्योग के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। इस पहल से 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत देश में खेल सामग्री निर्माण करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने की संभावना है। सरकार के 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के लिए 924.35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसके लिए पिछले वर्ष आवंटित राशि 1000 करोड़ रुपये थी, लेकिन अंतिम व्यय 700 करोड़ रुपये रहा। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सहायता राशि इस वर्ष 28.05 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 78 प्रतिशत की वृद्धि है। राष्ट्रमंडल खेल इस वर्ष जुलाई-अगस्त में ग्लासगो में होंगे।

खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 40 करोड़ की

राष्ट्रीय खेल विकास कोष में योगदान राशि को तीन करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि सरकार ने इस वर्ष खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 28 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये कर दिया है। राष्ट्रीय खेल संघों के लिए सहायता राशि में भी मामूली वृद्धि की गई है, जो 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 425 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा, ''यह मिशन मूलभूत, मध्यवर्ती और विशिष्ट स्तरों के प्रशिक्षण केंद्रों के सहयोग से एकीकृत प्रतिभा विकास, प्रशिक्षकों और सहायक स्टाफ का व्यवस्थित विकास, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और मंच प्रदान करने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग का आयोजन तथा प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए खेल संरचना के विकास को सुगम बनाएगा।''

'खेलो इंडिया मिशन' शुरू करने का प्रस्ताव

सीतारमण ने अगले दशक में प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों के व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'खेलो इंडिया मिशन' शुरू करने के प्रस्ताव रखा जिससे जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए सरकार के प्रमुख 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि यह मिशन आपस में जुड़े विभिन्न माध्यमों से एकीकृत प्रतिभा विकास कार्यक्रम को सुगम बनाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभा पहचान के लिए सभी आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना था। सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण के दौरान कहा, ''खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से खेल प्रतिभाओं को निखारने की पहल को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव करने के लिए 'खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं।''

कुश्ती कोच की नजर में बजट

कुश्ती कोच मनदीप ने बताया कि खेलो इंडिया को मिशन मोड में लाना यह दर्शाता है कि सरकार केवल प्रतिभा खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले 10 वर्षों के लिए बुनियादी ढांचे, खेल विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण को एकीकृत कर रही है। यह जमीनी स्तर के खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि को 28 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता राशि में वृद्धि करना यह सुनिश्चित करेगा कि एथलीटों को उनकी मेहनत का उचित सम्मान और ट्रेनिंग के लिए जरूरी संसाधन मिलते रहें। युवा हॉस्टलों के बजट में 1.10 करोड़ से सीधे 19.20 करोड़ की बढ़ोतरी और एनएसएस के बजट में वृद्धि दर्शाती है कि सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास और खेल अनुशासन को लेकर गंभीर है।

खबर संक्षेप

महिला अंडर-17 टीम के सामने बांग्लादेश की चुनौती

पोखरा। भारतीय टीम सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के अपने दूसरे मुकाबले में सोमवार को जब पोखरा रंगशाला स्टेडियम में मजबूत बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश एक मैच शेष रहते फाइनल में जगह पक्की करने की होगी। इस साल के आखिर में चीन में होने वाले एएफसी अंडर-17 महिला एशियाई कप की तैयारियों में लगी पामेला कॉन्टी की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत मेजबान नेपाल के खिलाफ कड़े मुकाबले में 1-0 की जीत के साथ की थी। भारतीय टीम अगर इस मैच को जीतने में सफल रही तो फाइनल के लिए उसका दावा लगभग पक्का हो जाएगा। भारत को इससे पहले मेजबान नेपाल से कड़ी चुनौती मिली लेकिन पर्ल फर्नांडिस ने 49वें मिनट में गोल कर मैच में बड़ा अंतर पैदा किया।

जूनियर पुरुष स्कीट टी2 ट्रायल में पंजाब के निशानेबाज शीर्ष पर

नई दिल्ली। पंजाब के हरवीराज सिंह, हरजीज सिंह अटवाल और गुरफतेह सिंह संधू ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर शॉटगन राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स एक और दो में जूनियर पुरुष स्कीट टी2 के फाइनल में क्लीन स्वीप किया। अनंतजीत सिंह नरूका ने पुरुष वर्ग के ट्रायल दो

फाइनल में 36 में से 36 का परफेक्ट स्कोर कर ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया को एक अंक से पछाड़ते हुए खिताब जीता। यशस्वी राठौड़ ने महिला ट्रायल्स दो में सिर्फ एक निशाना चूकते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। क्वालीफिकेशन में 120 अंक के साथ शीर्ष पर रहने वाले अनंतजीत ने फाइनल में सटीक प्रदर्शन किया। ज्योतिरादित्य ने भी 34वें टारगेट तक परफेक्ट स्कोर बनाए रखा, लेकिन 35वें निशाने में चूकने के कारण 36 में से 35 अंक ही हासिल कर सके। अभय सिंह सेखों ने 30 निशाने के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

खिलाड़ियों को करना होगा दिनचर्या में बदलाव : सैंटनर

तिरुवनंतपुरम। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि उनकी टीम टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उपमहाद्वीप में अपने पिछले अनुभव और विभिन्न परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की अपनी क्षमता पर भरोसा करेगी। न्यूजीलैंड ने सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले भारत के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले।

गेंदबाजों और वोल्टवार्ट ने दिल्ली कैपिटल्स को जीत और एलिमिनेटर में जगह दिलाई

वडोदरा। मारिजेन कैप की अगुआई में गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन के बाद लॉरा वोल्वार्ट की उम्दा पारी से दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग में रविवार को यहां यूपी वारियर्स को पांच विकेट से हराकर एलिमिनेटर में जगह बनाई। दिल्ली की टीम अब एलिमिनेटर में मंगलवार को गुजरात जाइंट्स से भिड़ेगी। वारियर्स के 123 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने दो जीवनदान का फायदा उठाने वाली वोल्वार्ट की 36 गेंद में सात चौकों से 47 रन की पारी और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (29 रन, 33 गेंद, दो चौके) के साथ उनकी दूसरे विकेट की 73 रन की साझेदारी से 18.4 ओवर में पांच विकेट पर 126 रन बनाकर जीत दर्ज की। कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 18 गेंद में पांच चौकों से नाबाद 34 रन की पारी खेलकर दिल्ली की जीत सुनिश्चित की। दिल्ली कैपिटल्स ने इस जीत से आठ अंक के साथ मुंबई इंडियन्स (छह अंक) को पछाड़कर तीसरे स्थान पर रहते हुए एलिमिनेटर में जगह बनाई। रॉयल

चैलेंजर्स बेंगलुरु (12) और गुजरात जाइंट्स (10) शुरुआती दो स्थान पर रहे। कैप (30 रन पर तीन विकेट), श्री चरणी (22 रन पर दो विकेट) और चिनेल हेनरी (25 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने यूपी वारियर्स की टीम आठ विकेट पर 122 रन ही बना सकी।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्प्ले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

22 साल के अल्कारेज ने एक सेट गंवाने के बाद की वापसी, जोकोविच को दी शिकस्त

अल्कारेज ने कम्पलीट किया कॅरियर स्लैम, तोड़ा जोकोविच का सपना, जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन

एजेंसी ▶▶| मेलबर्न

कार्लोस अल्कारेज रविवार को फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम करके कॅरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम- ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे कॅरियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच की मेलबर्न पार्क में फाइनल में यह पहली हार है। इससे पहले उन्होंने यहां अपने सभी 10 फाइनल में जीत दर्ज की थी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अल्कारेज ने रविवार को पहला सेट गंवाया लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की। 22 साल के स्पेन के खिलाड़ी ने 38 साल के जोकोविच पर दबाव बनाए रखा।

कोच को गले लगाने दौड़े कार्लोस

जीत पक्की करने के बाद अल्कारेज ने हाथ से रैकेट छोड़ दिया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गए और अपने हाथ सिर पर रख लिए। जोकोविच से हाथ मिलाने के लिए नेट पर जाने से पहले वह कुछ सेकेंड वहीं रुके। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बातें कीं और जोकोविच स्पेन के खिलाड़ी को बधाई देते हुए मुस्कुराए। इसके बाद नया चैंपियन कोर्ट के एकतरफ लगी कुर्सियों पर बैठे अपने कोच को गले लगाने के लिए दौड़ा और बाद में स्टैंड में अपने पिता और टीम के दूसरे सदस्यों को भी गले लगा।

■ कॅरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने कार्लोस

अल्कारेज ने तोड़ा डॉन बज का रिकॉर्ड

अल्कारेज 22 साल और 272 दिन की उम्र में चारों ग्रैंडस्लैम का एकल खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने। उन्होंने 1938 की फ्रेंच चैंपियनशिप में डॉन बज का बनाया रिकॉर्ड तोड़ा जब वह 22 साल और 363 दिन के थे। स्पेन के अल्कारेज ने अब तक सात ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन के अलावा दो-दो विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन शामिल हैं।

जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम पर अल्कारेज ने लगाई रोक

दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पांच सेट में कड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की तलाश में तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों ने जबरदस्त फिटनेस, खेल और स्टेमिना का नजारा दिखाया। कोई भी खिलाड़ी बड़े अंकों पर हार मानने को तैयार नहीं था। स्पेन के खिलाड़ी ने 16 ब्रेक प्वाइंट में से पांच का फायदा उठाया जबकि जोकोविच छह ब्रेक प्वाइंट में से सिर्फ दो को ही अंक में बदल सके। जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब जीतने के अभियान पर एक बार फिर अल्कारेज और यानिक सिनर में से एक ने रोक लगाई। इन दोनों ने मिलकर पिछले नौ ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं। जोकोविच ने सेमीफाइनल में सिनर को हराया था और ओपन युगल में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनने की राह पर थे लेकिन अल्कारेज ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप मैच नहीं खेलेगा पाक

पाकिस्तान सरकार का ऐलान, टूर्नामेंट में भाग लेगा

एजेंसी ▶▶| कराची

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने बहुप्रतीक्षित ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी लेकिन सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम, जिसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। सरकार के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दिए गए इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। विश्व निकाय ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा, क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में ''मैदान पर नहीं उतरेगी''।

पाक के बहिष्कार के नतीजेः प्रतिबंध, नुकसान की भरपाई, पीएसएल पर रोक, डब्ल्यूटीसी अंक नहीं

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पाकिस्तान के खिलाफ कई सजा देने वाले कदम उठा सकता है। यह कार्रवाई पाकिस्तान सरकार के भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने के फैसले के बाद की जा सकती है और इसमें इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के आगामी सत्र से टीम पर प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है। अन्य सजा में शीर्ष सदस्य देशों का पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने से इनकार करना, भारी वित्तीय जुर्माना और साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टी20 विश्व कप से बांग्लादेश के बाहर होने के फैसले का साथ देते हुए 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ अपना ग्रुप लीग मैच नहीं खेलने का फैसला किया है जबकि आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ उसका तटस्थ स्थल पर मैच खेलने का अनुबंध है जो बाध्यकारी है। आईसीसी बोर्ड के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ''पीसीबी ने अभी तक आईसीसी को आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया है लेकिन चूंकि आधिकारिक घोषणा हो चुकी है इसलिए आईसीसी के कुछ सख्त कार्रवाई करने की उम्मीद है।

स्क्वैश ऑन फायर

सबरीना को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंचीं अनाहत

एजेंसी ▶▶| वाशिंगटन

अनाहत सिंह ने वाशिंगटन में स्क्वैश ऑन फायर ओपन में अमेरिका की सबरीना सोभी को 3-1 से मात दी। इसी के साथ अनाहत ने पीएसए ब्रॉन्ज-लेवल इवेंट के अपने पहले फाइनल में जगह बना ली है। अनाहत सिंह ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 23 सबरीना को 11-9, 11-3, 9-11, 11-5 से शिकस्त दी। खिताबी मुकाबले में 17 वर्षीय अनाहत का सामना टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 10 इंग्लैंड की जॉर्जीना कैनेडी से होगा। इससे पहले, शनिवार को अनाहत ने 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए नंबर 2 सीड सना इब्राहिम को शिकस्त देकर स्क्वैश ऑन फायर ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय वर्ल्ड नंबर 31 और सातवीं सीड खिलाड़ी ने मैच में वापसी करते हुए, तीसरे और चौथे गेम दोनों में 6-5 के घाटे को पलट दिया, और पीएसए ब्रॉन्ज-लेवल इवेंट में मिस्र की वर्ल्ड नंबर 17 सना इब्राहिम को 8-11, 8-11, 11-7, 11-8, 11-7 से मात दी थी।

बल्लेबाजी में बदलाव से मिली फॉर्म में वापसी में मददः सूर्यकुमार

तिरुवनंतपुरम। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली। सूर्यकुमार ने शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड पर भारत की 4-1 से जीत में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेली। सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। वह इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाए और उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद सूर्यकुमार ने आत्मचिंतन किया और अपने खेल में कुछ बदलाव किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार पारियों में वह केवल 34 रन बनाए थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 12 रन था। सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 46 रन से जीत के बाद कहा, 'दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद मुझे ब्रेक मिला। मैंने घर लौटने पर अपना किट बैग एक तरफ रखा और नौ-दस दिन तक आराम किया।'

अंडर-19 विश्व कपः कनिष्क के हरफनमौला खेल से पाकिस्तान को हराकर भारत सेमीफाइनल में

भाषा ▶▶| बुलावायो

युवा कनिष्क चौहान के हरफनमौला खेल के दम पर भारत ने अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स मुकाबले में रविवार को यहां चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 58 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारत के सामने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की चुनौती होगी। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने होंगे। कनिष्क ने बल्ले से 29 गेंद में 35 रन की पारी खेलने के अलावा आठवें विकेट लिए खिलान पटेल (15 गेंद में 21 रन) के साथ 50 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की जिससे टीम ने 49.5 ओवर में 252 रन बनाये। पाकिस्तान को भारत से बेहतर नेट रन रेट हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाने

के लिए 33.3 ओवर में लक्ष्य हासिल करना था लेकिन टीम ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कभी ऐसा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। पाकिस्तान ने 33.3 ओवर में चार विकेट पर 167 रन बनाये थे और फिर पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 रन पर आउट हो गयी। गेंदबाजी विभाग में कनिष्क ने 10 ओवर में महज 30 रन देकर एक विकेट चटकाते हुए पाकिस्तान टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने इस दौरान 40 डॉट गेंदें डाली। पिच से स्पिनरों को मदद मिलने के बीच बाएं हाथ के स्पिनर खिलान पटेल (9.2 ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट) और कप्तान आयुष म्हात्रे (8 ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट) ने भी बीच ओवरों में रन गति को पूरी तरह बांधे रखा।

- पाकिस्तान को 58 रन से हराया
- वेदांत की फिफ्टी, आयुष म्हात्रे और खिलन पटेल को 3-3 विकेट

थाईलैंड मास्टर्स में हटी दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह

देविका ने जीता अपना पहला सुपर 300 खिताब

एजेंसी ▶▶| बैंकॉक

युवा शटलर देविका सिहाग ने 250,000 डॉलर इनामी थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता।

हरियाणा की रहने वाली 20 वर्षीय खिलाड़ी देविका तब 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी, जब विश्व में 68वें नंबर की खिलाड़ी और दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इससे भारतीय खिलाड़ी अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में सफल रही।

देविका के लिए फाइनल रहा शानदार

देविका के लिए फाइनल शानदार रहा लेकिन उनकी प्रतिद्वंदी गोह को पीड़ा झेलनी पड़ी। वह फाइनल से पहले तीन गेम तक चले चार मैच खेलने के बाद थकी हुई लग रही थीं और उन्हें कोर्ट को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले दो वर्षों से फॉर्म और फिटनेस के लिए संघर्ष कर रही गोह ने शनिवार को भी थकान की शिकायत की थी और उन्हें कोर्ट में चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी। उनका बायां पैर हिल नहीं पा रहा था और वह लगातार परेशान दिख रही थीं। देविका ने फाइनल में शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार रिटर्न और बेहतरीन स्ट्रोक के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली। एक नेट कॉर्ड की बदौलत गोह ने अपना पहला अंक हासिल किया।

मलेशियाई खिलाड़ी लग रही थीं थकी हुई

मलेशियाई खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी के खेल को समझ ही नहीं पा रही थी। मलेशियाई खिलाड़ी थकी हुई लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनमें ऊर्जा नहीं बची है। देविका ने शानदार क्रॉस के दम पर 13 गेम प्वाइंट हासिल किए और बैकहैंड क्रॉस से पहला गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में देविका ने जल्द ही 6-3 की बढ़त बना ली। मलेशिया की खिलाड़ी असहज दिख रही थी और उन्होंने आखिर में मैच से हटने का फैसला कर दिया। देविका ने पिछले कुछ समय से शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अगस्त 2025 में मलेशिया इंटरनेशनल में अपना पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता था। इसके बाद उन्होंने 2025 में विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत की मिश्रित टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम योगदान दिया। वह पिछले सत्र में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 में उपविजेता रही थी जबकि 2024 में चार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। इनमें स्वीडिश ओपन और पुर्तगाल इंटरनेशनल भी शामिल हैं, जहां वह विजेता रही थी।

खबर संक्षेप

मणिपुर के 20 विधायकों की दिल्ली में मीटिंग

नई दिल्ली। मणिपुर के 20 से अधिक भाजपा विधायकों ने रविवार को राज्य इकाई के अध्यक्ष के साथ

इंफाल से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। वे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बड़ी बैठक में शामिल होंगे। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष अधिराजमायुम शारदा देवी ने कहा कि सभी एनडीए विधायकों को बुलाया गया है। प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन होगा।

शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग, गिरफ्तार

मुंबई। यहां के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने

आई है। जिस समय यह फायरिंग हुई, उस वक्त शेट्टी घर के अंदर ही मौजूद थे। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला आरोपी केवल एक ही था।

ट्रंप की पत्नी मेलानिया की फिल्म रही फ्लाप

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री 'मेलानियाः 20 डेज

टू हिस्ट्री' शुक्रवार को रिलीज हुई। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हुई। मेलानिया की डॉक्यूमेंट्री में जनवरी 2025 में डोनल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से ठीक 20 दिन पहले की कहानी दिखाई गई है।

रांची के मां-बेटे की पुरी समुद्र में दर्दनाक मौत

रांची। ओडिशा के पुरी में छुट्टियां मनाने आए रांची के एक प्रतिष्ठित परिवार के लिए शनिवार काल

बनकर आया।चक्रतीर्थ रोड स्थित पिंक हाउस क्षेत्र में समुद्र स्नान के दौरान मां को डूबता देख उसे बचाने कूदा इकलौता बेटा भी लहरों की भेंट चढ़ गया। इस हृदयविदारक घटना ने जहां रांची के आरएसएस परिवार में शोक की लहर दौड़ा दी है।

विजया 2 मासूम बच्चों संग ट्रेन के आगे कूदी

हैदराबाद। यहां रविवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना हुई। चेरलापल्ली रेलवे स्टेशन के पास

38 साल की पी. विजया ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ मालगाड़ी के आगे छलांग लगा दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शनिवार रात करीब 12:40 बजे की है, जब सनतनगर जा रही मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी गांधी अस्पताल के मुर्दाघर में भेज दिया गया है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

बजट में भूटान, श्रीलंका व अफ्रीकी देशों को मदद के लिए राशि का ऐलान

दूतावासों-मिशन्स के लिए 5059.30 और पासपोर्ट व आव्रजन व्यवस्था के लिए 2435.13 करोड़ दिए

पड़ोसी और अन्य सहयोगी देशों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के लिए बजट का ऐलान कर दिया है। इसमें भारत के पड़ोसी और अन्य सहयोगी देशों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की गई है। भूटान से लेकर श्रीलंका और बांग्लादेश से लेकर अफ्रीकी देशों तक की मदद के लिए राशि का ऐलान किया गया है। हालांकि, बांग्लादेश के लिए सहायता राशि में कटौती की चर्चा है। पिछले कुछ समय से भारत के बाग्लादेश के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे हैं।

पड़ोसी देशों के रिश्तों को परखा

इस बजट में एक चौंकाने वाली बात यह रही कि चाबहार बंदरगाह के लिए सहयोग राशि वाली पंक्ति को 2026-27 के लिए खाली छोड़ा दिया गया। ऐसे में चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसके लिए सरकार ने फिलहाल कोई राशि जारी नहीं की है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि भारत इस परियोजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस पर कोई बात नहीं की गई है।

चाबहार बंदरगाह परियोजना

इन देशों की मदद पिछले साल के मुकाबले परिवर्तित

लातिन अमेरिकी देशों के लिए आवंटन को दो गुना किया

मंगोलिया के बजट में 5 गुना वृद्धि देखी गई है। लातिन अमेरिकी देशों के लिए आवंटन को सीधे दोगुना कर दिया गया है। सरकार दक्षिण अमेरिका में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने पर जोर दे रही है। भूटान कोसहायता राशि में मूल्य के मामले में सबसे बड़ी वृद्धि (138.56 करोड़) हुई है, हालांकि प्रतिशत के लिहाज से यह 6.44% है। अफ्रीकी देशों (225 करोड़) और सेशेल्स (19 करोड़) के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आपदा प्रबंधन के लिए भारत ने इस बार राशि में किया इजाफा

भारत ने विदेश में आपदा प्रबंधन के लिए सहायता के तौर पर 2025-26 के 64 करोड़ के मुकाबले 2026-27 में 80 करोड़ की राशि आवंटित की है। भारत ने बीते साल इस राशि के जरिए श्रीलंका की दित्वाह चक्रवात से निपटने में मदद की। म्यांमार और अफगानिस्तान की भूकंप के बाद हुई तबाही से निपटने में भी मदद की गई। सरकार ने इस राशि के जरिए कुछ देशों को राहत सामग्री भी पहुंचाई है।

बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार की मदद घटी

बांग्लादेशः बांग्लादेश की सहायता राशि में 50 प्रतिशत कटौती की गई है। **मालदीव और म्यांमारः** इन दोनों देशों के बजट में 50-50 करोड़ रुपए की कमी की गई है।

विदेश की बाकी योजनाओं पर ऐसा रहा बजट

- केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय से जुड़े सचिवालयों के लिए 761.21 करोड़ का बजट तय किया।
- दूतावासों-मिशन्स के लिए 5059.30 करोड़ तय किए गए।
- पासपोर्ट और आव्रजन व्यवस्था के लिए 2435.13 करोड़ आवंटित किए गए।
- विदेश में रह रही भारतीय महिलाओं के कल्याण की योजनाओं के लिए पांच करोड़ दिए गए।
- मंत्रालय के अन्य खर्चों के लिए 1265 करोड़ बजट में रखे गए हैं।

चाबहार बंदरगाह के लिए राशि आवंटित नहीं की

ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि उससे व्यापार करने वाले देशों पर 25 फीसदी के अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। भारत पर 50 फीसद टैरिफ लगाया जा चुका है। इसमें 25 फीसदी आयात शुल्क व्यापार के मसले पर, जबकि अतिरिक्त 25 फीसदी रूस से तेल खरीद को लेकर लागू है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि भारत ने ट्रंप के दबाव में ईरान के चाबहार बंदरगाह पर नियंत्रण छोड़ दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चाबहार पर जनता के करीब 1100 करोड़ लगाए थे, जो कि अब बर्बाद हो चुके हैं। बजट में इस बंदरगाह परियोजना के लिए कोई आवंटन नहीं है।

पीएम मोदी ने लुधियाना को दी सौगात

हलवारा एयरपोर्ट का लोकार्पण अगले माह से होगा संचालन

आदमपुर अब जाना जाएगा श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट

एजेंसी ⏭ लुधियाना

कई वर्षों के इंतजार के बाद लुधियाना के लोगों को नया एयरपोर्ट मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर शहर को बड़ी कनेक्टिविटी की सौगात दी है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से लुधियाना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच हवाई यात्रा अब और आसान हो जाएगी। मार्च से हलवारा एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा। शुरुआती चरण में लुधियाना से दिल्ली और दिल्ली से लुधियाना के बीच सप्ताह में पांच दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। एयरपोर्ट के चालू होने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे लुधियाना की देश के अन्य बड़े शहरों से हवाई संपर्क की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

संत निरंजन दास के पैर छुए

प्रधानमंत्रीरविदासिया समाज के जालंधर स्थित सबसे बड़े धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्लां पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां संत निरंजन दास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें सम्मानित किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट कर दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने इसके बाद लुधियाना के हलवारा स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुरु रविदास जी ने समाज को एकजुट किया है। उन्होंने कहा कि हमारी भाजपा सरकार ने संत निरंजन दास को सम्मानित किया है।

पंजाब की धरती को नमनः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने पंजाबी में कहा कि मैं पंजाब की धरती को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता गुरु रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। पीएम मोदी ने इस दौरान रविदास की वाणी से 3 श्लोक पढ़े। साथ ही काशी (वाराणसी), मध्यप्रदेश और पंजाब में संत रविदास की सेवा करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर रखा गया है।

बलूचिस्तान पर हमले के पाकिस्तान के ओछे आरोप को भारत ने किया सिरे से खारिज

बोले रणधीर जायसवाल, ये क्षेत्र में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की पुरानी पाकिस्तानी कोशिश से ज्यादा और कुछ नहीं है

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

बलूचिस्तान में 31 जनवरी को एक के बाद एक हुए कुल 14 भीषण हमलों को लेकर भारत पर आरोप मढ़ने वाले पाकिस्तान को नई दिल्ली ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार को दो टूक अंदाज में कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए तमाम आधारहीन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। यह उसकी अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की पुरानी रणनीति से ज्यादा और कुछ नहीं है। उन्होंने पाक को नसीहत देते हुए कहा कि हर बार किसी भी हिंसात्मक घटना के होने पर भारत के खिलाफ ओछे दावे करने से बेहतर होगा कि वह क्षेत्र में अपने लोगों की लंबे समय से बनी हुई मांग पर ध्यान केंद्रित करे। क्योंकि इलाके में आम-जनता के दमन, उनके खिलाफ की जाने वाली क्रूरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में शत्रु राष्ट्र के रिकॉर्ड से पूरी दुनिया भली-भांति परिचित है।

पाक गृहमंत्री ने भारत पर मढ़े झूठे आरोप

गौरतलब है कि पाकिस्तान के दर्जनभर शहरों में किए गए इन हमलों को बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने अंजाम दिया है। जिसमें उनके निशाने पर पाकिस्तान सेना और अन्य सुरक्षाकर्मी रहे। हमलों में करीब 7 दर्जन से अधिक यानी 85 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है।

बलूचिस्तान कई दशकों से पाकिस्तानी शासन से अपनी आजादी की मांग कर रहा है। जिसकी क्षेत्र में सबसे बड़ी आवाज बीएलए ही है। बीते वक्त में पाक सेना ने बड़े पैमाने पर बीएलए के कई लड़ाकों को अलग-अलग हमलों में मार गिराया था। जिसके बाद से दोनों पक्षों में तनाव जारी है।

वहीं, 1 फरवरी को पाकिस्तान के इंटीरियर (आंतरिक मामलों) मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि कल बलूचिस्तान में हुए इन हमलों के पीछे भारत का हाथ था। बीएलए के इन हमलों में कम से कम डेढ़ दर्जन पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाक मीडिया ने दावा किया है कि इन हमलों में 92 बीएलए लड़ाकों की मौत हुई है।

देश में अलर्ट पर सेनाएं

समूचे घटनाक्रम के बीच भारत में आतंकवादी हमलों की आशंका भी बढ़ गई है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर अब तक सशस्त्र सेनाएं देश की सभी सीमाओं की पूरी मुस्तैदी के साथ चौबीसों घंटे सुरक्षा करने में लगी हुई हैं। वर्तमान समय में भी उनकी तैनाती में कोई खास बदलाव नहीं आया है। जबकि दूसरी ओर अर्धसैन्य बलों द्वारा आंतरिक स्तर पर भारत के सुरक्षा घेरे को 360 डिग्री मजबूती प्रदान की जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी दृढ़ता के साथ लागू है। ऐसे में किसी भी हमले का तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

पत्रकारों से बातचीत में कहा- हमने पहले ही डील तय कर ली

भारत अब ईरान से नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल, डील हो गई पक्की

एजेंसी ⏭ वॉशिंगटन/ नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तेल खरीद को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ इस बारे में डील की गई है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने पहले ही वह डील कर ली है। डील का कॉन्सेप्ट तय हो गया है। ट्रंप का बयान अमेरिका के नई दिल्ली को यह संकेत देने के एक दिन बाद आया है कि वह रूसी कच्चे तेल के कम आयात की भरपाई के लिए जल्द ही वेनेजुएला से तेल खरीदना फिर से शुरू कर सकता है। वहीं, ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मध्य पूर्व में 'क्षेत्रीय युद्ध' को जन्म देगा, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है। यह बयान तब सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्लामी गणराज्य पर सैन्य हमले की धमकी दी है।

हरिभूमि कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक देवेन्द्र सिंह बाल्यान द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशंस, चुलियाना मोड़, दिल्ली रोड, रोहतक-124517 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, 129, ट्रांसपोर्ट सैंटर, पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : डॉ.हिमांशु द्विवेदी। आरएनआई नं 69631/1998, फोन : 011-40451115/16, 40451109